नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 144
दि. 26.02.2026,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

पाठ्यपुस्तक पर उठा सवाल, न्यायपालिका की गरिमा पर सख्त हुआ देश का सर्वोच्च न्यायालय

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश की शिक्षा व्यवस्था और न्यायपालिका की गरिमा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विवाद उस समय सामने आया, जब राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की कक्षा आठ की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में न्यायपालिका से संबंधित विवादित सामग्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर आपत्ति जताई। इस मामले में न्यायपालिका की प्रतिष्ठा और छात्रों को दिए जाने वाले शैक्षिक संदेश को लेकर शीर्ष अदालत की सख्ती के बाद सरकार ने भी तुरंत संज्ञान लेते हुए संबंधित सामग्री को हटाने का फैसला किया है। यह विवाद न केवल शिक्षा जगत में चर्चा का विषय बन गया है, बल्कि इसने न्यायपालिका और शिक्षा के संबंधों को लेकर एक व्यापक बहस को जन्म दे दिया है। सूत्रों के अनुसार, एनसीईआरटी की कक्षा आठ की पुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से संबंधित कुछ अंश शामिल किए गए थे, जिन पर न्यायपालिका और कानूनी समुदाय के कई सदस्यों ने गंभीर चिंता व्यक्त की। इस सामग्री को लेकर यह आशंका जताई गई कि इससे छात्रों के मन में न्यायपालिका की छवि प्रभावित हो सकती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए परिषद ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पुस्तक को अपनी आधिकारिक वेबसाइट से हटा दिया है। साथ ही, इस अध्याय को

तैयार करने वाले विषय विशेषज्ञों और इसे मंजूरी देने वाले अधिकारियों की भूमिका की समीक्षा के लिए एक आंतरिक बैठक भी बुलाई गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न न हो।

हालांकि, परिषद के अध्यक्ष दिनेश प्रसाद सकलानी ने इस मामले पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है। परिषद के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी यह कहते हुए प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया कि मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है। इससे यह स्पष्ट होता है कि परिषद इस मुद्दे को अत्यंत संवेदनशील मानते हुए कानूनी प्रक्रिया का सम्मान कर रही है और उचित निर्णय की प्रतीक्षा कर रही है। सरकारी सूत्रों ने इस पूरे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एनसीईआरटी एक स्वायत्त संस्था है और उसे पाठ्यक्रम तैयार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन इस स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। उन्होंने कहा कि यदि भ्रष्टाचार जैसे संवेदनशील विषय को पाठ्यपुस्तक में शामिल करना आवश्यक था, तो इसे केवल न्यायपालिका तक सीमित रखने के बजाय कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका – तीनों संवैधानिक अंगों के संदर्भ में संतुलित रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। सरकार का यह दृष्टिकोण इस बात को दर्शाता है कि शिक्षा में संतुलन और निष्पक्षता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, ताकि छात्रों को सही और समग्र जानकारी मिल सके। इस मामले में देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने भी कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी को भी न्यायपालिका जैसी महत्वपूर्ण संस्था की गरिमा को ठेस पहुंचाने या उसे बदनाम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उनकी यह टिप्पणी न्यायपालिका की प्रतिष्ठा और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

यह मामला उस समय शीर्ष अदालत के समक्ष आया, जब वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने संशोधित पाठ्यपुस्तक की सामग्री पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने अदालत को बताया कि कानूनी बिरादरी के कई सदस्य इस बात से परेशान हैं कि स्कूली छात्रों को न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ाया जा रहा है। उनका मानना था कि इस प्रकार की सामग्री से छात्रों के मन में न्यायपालिका के प्रति गलत धारणा बन सकती है। उन्होंने इस स्थिति को निंदनीय बताते हुए अदालत से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया।

इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि वह पहले से ही इस विवाद से अवगत हैं और उन्हें न्यायपालिका के कई सदस्यों से इस संबंध में पत्र प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि कई उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों ने भी इस सामग्री पर चिंता व्यक्त की है।

लोकतंत्र की मर्यादा पर सवाल: विरोध प्रदर्शन के बीच स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज घायल, सियासत में बढ़ा तनाव

(जीएनएस)। कोच्चि। केरल की राजनीति में उस समय अचानक तनाव और हलचल बढ़ गई, जब राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज कांग्रेस से जुड़े छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हो गईं। यह घटना कन्नूर रेलवे स्टेशन पर उस समय हुई, जब मंत्री अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत ट्रेन पकड़ने पहुंची थीं। विरोध प्रदर्शन की इस घटना ने न केवल राज्य की राजनीतिक स्थिति को गर्मा दिया, बल्कि लोकतांत्रिक विरोध और उसकी मर्यादा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

घटना के प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस सूत्रों के अनुसार, मंत्री वीना जॉर्ज जैसे ही रेलवे स्टेशन पर पहुंचीं, वहां पहले से मौजूद कांग्रेस के छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों की संख्या अचानक बढ़ गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसी दौरान मंत्री भीड़ के बीच फंस गईं और धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई। इस अफरा-तफरी में मंत्री के हाथ और गर्दन में चोटें आईं। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और मंत्री को सुरक्षित बाहर निकाला।

घटना के समय वहां मौजूद केरल विधानसभा के अध्यक्ष ए.एन. शमसीर ने पत्रकारों को बताया कि मंत्री को भीड़ से निकालते समय उन्हें चोट लगी। उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे लोकतांत्रिक

व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। टीवी चैनलों पर प्रसारित वीडियो में भी साफ देखा गया कि मंत्री प्रदर्शनकारियों के बीच घिरी हुई थीं और पुलिस उन्हें सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रही थी।

घटना के तुरंत बाद मंत्री वीना जॉर्ज को कन्नूर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज शुरू किया गया। जानकारी के अनुसार, उनकी स्थिति स्थिर है, लेकिन उन्हें एहतियातन गहन चिकित्सा इकाई में रखा गया है ताकि उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा सके। पी. जयराजन ने मीडिया को बताया कि डॉक्टरों की एक टीम मंत्री की निगरानी कर रही है और उनकी हालत में सुधार हो रहा है।

इस घटना के पीछे पिछले कुछ दिनों से चल रहा राजनीतिक विवाद भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जा रहा है। हाल के दिनों में राज्य में कुछ मरीजों से जुड़े चिकित्सा लापरवाही के मामलों को लेकर विपक्ष सरकार और स्वास्थ्य विभाग की आलोचना कर रहा था। कांग्रेस और उसके छात्र संगठन केरल स्टूडेंट्स यूनियन ने इन घटनाओं को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर रखा था। इसी विरोध के तहत कन्नूर रेलवे स्टेशन पर भी प्रदर्शन आयोजित किया गया था।

इस घटना के बाद केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसकी निंदा की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना एक अधिकार है, लेकिन किसी मंत्री या जनप्रतिनिधि पर हमला करना या उन्हें घायल करना किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। मुख्यमंत्री ने इसे कांग्रेस की घृणित राजनीति का उदाहरण बताते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करती हैं।

मुख्यमंत्री विजयन ने अपने बयान में कहा कि मंत्री वीना जॉर्ज पर हमला उस समय हुआ, जब वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही थीं। उन्होंने कहा कि यह घटना न केवल एक मंत्री पर हमला है, बल्कि यह राज्य की लोकतांत्रिक व्यवस्था और शासन प्रणाली पर भी हमला है। उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया कि घटना की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

इस घटना ने राज्य की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन एक आवश्यक और महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन यह विरोध शांतिपूर्ण और मर्यादित होना चाहिए। जब विरोध हिंसक रूप ले लेता है, तो यह लोकतंत्र की आत्मा को नुकसान पहुंचाता है।

केरल, जो अपनी राजनीतिक जागरूकता और सक्रिय लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए जाना जाता है, वहां इस तरह की घटना का होना चिंता का विषय है। यह घटना यह भी दिखाती है कि राजनीतिक मतभेद कभी-कभी किस तरह टकराव में बदल जाते हैं। यह आवश्यक है कि सभी राजनीतिक दल और संगठन लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करें और विरोध प्रदर्शन के दौरान संयम बनाए रखें।

मंत्री वीना जॉर्ज, जो अपने कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा चुकी हैं, इस घटना के बाद भी अपने कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। उनके समर्थकों और सहयोगियों ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है और इस घटना की कड़ी निंदा की है।

यह घटना केवल एक राजनीतिक विवाद नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र की उस बुनियादी भावना की परीक्षा भी है, जिसमें असहमति को सम्मानपूर्वक व्यक्त किया जाता है।

दोस्ती का ऐतिहासिक आलिंगन: तेल अवीव में पीएम मोदी का भव्य स्वागत, भारत-इजरायल संबंधों को नई ऊंचाई देने का संकल्प

(जीएनएस)। तेल अवीव। वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और कूटनीतिक सक्रियता का एक और महत्वपूर्ण अध्याय उस समय जुड़ गया, जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर इजरायल पहुंचे। तेल अवीव स्थित बेन गुरियन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर उनके आगमन के साथ ही भारत और इजरायल के बीच गहरी मित्रता और रणनीतिक साझेदारी का प्रतीकात्मक दृश्य देखने को मिला। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी पत्नी सारा नेतन्याहू के साथ प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें गले लगाकर अपने स्नेह और सम्मान का परिचय दिया। यह दृश्य केवल औपचारिक स्वागत नहीं था, बल्कि दो देशों के बीच विश्वास, सहयोग और मजबूत रिश्तों का जीवंत प्रतीक बन गया। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत पूरे सम्मान और पारंपरिक तरीके से किया गया। एयरपोर्ट पर मौजूद अधिकारियों और नागरिकों ने उत्साहपूर्वक उनका अभिनंदन किया। यह यात्रा केवल एक औपचारिक कूटनीतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह भारत और इजरायल के बीच वर्षों से विकसित होते रणनीतिक और भावनात्मक संबंधों की निरंतरता का प्रतीक है। वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री मोदी की पहली इजरायल यात्रा ने दोनों देशों के रिश्तों में एक नई ऊर्जा का संचार किया था, और अब उनकी दूसरी यात्रा इस साझेदारी को और अधिक गहराई और विस्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए उन्हें "प्रिय मित्र" कहा। यह संबोधन दोनों नेताओं के व्यक्तिगत संबंधों की मजबूती और आपसी विश्वास को दर्शाता है। आधुनिक कूटनीति में व्यक्तिगत संबंधों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, और मोदी-नेतन्याहू की मित्रता ने भारत-इजरायल संबंधों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच द्विपक्षीय वार्ता आयोजित की जाएगी, जिसमें रक्षा, सुरक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि, जल प्रबंधन, नवाचार, व्यापार और निवेश जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। भारत और इजरायल दोनों ही देश तकनीकी नवाचार और सुरक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, और यह सहयोग दोनों देशों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित हो रहा है। विशेष रूप से जल प्रबंधन और कृषि के क्षेत्र में इजरायल की उन्नत तकनीकों ने भारत के कई राज्यों में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद की है। प्रधानमंत्री मोदी इस यात्रा के दौरान इजरायल की संसद, जिसे नेसेट कहा जाता है, को भी संबोधित करेंगे। यह संबोधन केवल औपचारिक नहीं होगा, बल्कि यह दोनों देशों के लोकतांत्रिक मूल्यों, साझा दृष्टिकोण और भविष्य की साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता का संदेश देगा। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री मोदी इजरायल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे, जिससे दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच संवाद और सहयोग को और मजबूती मिलेगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी यात्रा से पहले कहा था कि भारत और इजरायल के बीच संबंध केवल रणनीतिक नहीं हैं, बल्कि यह साझा मूल्यों, नवाचार और प्रगति के दृष्टिकोण पर आधारित हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच सहयोग को और अधिक मजबूत करेगी और भविष्य में नई संभावनाओं के द्वार खोलेगी। आज भारत और इजरायल रक्षा सहयोग, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्टार्टअप और नवाचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदार बन चुके हैं।

इजरायल में इस यात्रा को लेकर विशेष उत्साह देखा गया। राजधानी यरुशलम और अन्य प्रमुख शहरों में भारतीय और इजरायली झंडों से सड़कों को सजाया गया है। संसद भवन और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से रोशन किया गया है, जो दोनों देशों के बीच मित्रता और सम्मान का प्रतीक है। स्थानीय नागरिकों द्वारा भारतीय अभिवादन "नमस्ते" के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करना इस बात का प्रमाण है कि दोनों देशों के बीच संबंध केवल सरकारों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि जनता के स्तर पर भी गहरी आत्मीयता मौजूद है। भारत और इजरायल के संबंध पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व रूप से मजबूत हुए हैं। रक्षा सहयोग से लेकर कृषि और तकनीकी नवाचार तक, दोनों देशों ने एक-दूसरे के साथ मिलकर कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है। यह यात्रा इन संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करने और भविष्य की नई संभावनाओं को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकती है।

तकनीकी जांच में अदालत का संयम, अहमदाबाद विमान हादसे पर हस्तक्षेप से किया इंकार

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश के सबसे दर्दनाक विमान हादसों में शामिल अहमदाबाद एयर इंडिया दुर्घटना से जुड़े मामले में न्यायपालिका ने एक महत्वपूर्ण और संतुलित निर्णय देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि तकनीकी जांच से जुड़े मामलों में अदालत का हस्तक्षेप सीमित होता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पिछले वर्ष 12 जून को हुए विमान हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट में अतिरिक्त तकनीकी विवरण शामिल करने की मांग की गई थी। इस फैसले ने न केवल न्यायिक प्रक्रिया की सीमाओं को स्पष्ट किया, बल्कि विशेषज्ञ संस्थाओं की भूमिका और महत्व को भी रेखांकित किया है। यह जनहित याचिका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके एक व्यक्ति द्वारा दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने अदालत से आग्रह किया था कि वह विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की प्रारंभिक रिपोर्ट का परीक्षण करे और उसमें इंजन के फ्लेम आउट यानी इंजन के बंद होने के सटीक समय और फ्यूल स्विच के संचालन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी शामिल करने के निर्देश दे। याचिका में यह तर्क दिया गया था कि इन तकनीकी पहलुओं का खुलासा दुर्घटना के वास्तविक कारणों को समझने में मदद करेगा और इससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि तकनीकी जांच और विशेषज्ञता से जुड़े मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप की एक निश्चित सीमा होती है। अदालत ने कहा कि यह याचिका इस सीमा से परे जाकर न्यायपालिका से ऐसे तकनीकी मामलों में हस्तक्षेप की मांग कर

रही है, जो विशेषज्ञ संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि इस प्रकार की मांग करना न्यायिक प्रक्रिया के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है और इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने अपने फैसले में यह भी उल्लेख किया कि यदि याचिकाकर्ता को जांच रिपोर्ट से संबंधित अतिरिक्त जानकारी चाहिए, तो इसके लिए सूचना का अधिकार कानून का उपयोग किया जा सकता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सूचना के अधिकार के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित करने का उचित कानूनी मार्ग उपलब्ध है और याचिकाकर्ता को पहले उसी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था। इस टिप्पणी से यह संदेश भी गया कि न्यायपालिका प्रक्रियागत नियमों और स्थापित कानूनी ढांचे का सम्मान करती है और उसी के अनुसार निर्णय देती है। इस मामले में अदालत ने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को दोहराते हुए कहा कि विशेषज्ञता से जुड़े मामलों में विशेषज्ञ संस्थाओं के निष्कर्षों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि जिस रिपोर्ट को पढ़ने और संशोधित करने की मांग की जा रही है, वह विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई है और अदालत के पास उस स्तर की तकनीकी विशेषज्ञता नहीं है कि वह उसमें हस्तक्षेप कर सके। यह टिप्पणी न्यायपालिका की विनम्रता और जिम्मेदारी दोनों को दर्शाती है, क्योंकि अदालत ने यह स्वीकार किया कि तकनीकी जांच का कार्य विशेषज्ञों के लिए ही उपयुक्त है।

याचिकाकर्ता के वकील ने सुनवाई के दौरान यह तर्क दिया कि दुर्घटना के पीछे इंजन सर्ज जैसी तकनीकी समस्या हो सकती है, और यदि इंजन के फ्लेम आउट और फ्यूल स्विच के संचालन का सटीक समय सामने आ जाए, तो दुर्घटना के कारणों की स्पष्ट तस्वीर सामने आ सकती है। हालांकि, अदालत ने इस तकनीकी तर्क पर विचार करने से इनकार कर दिया और कहा कि यह विषय विशेषज्ञों के दायरे में आता है और न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट केवल प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है और अंतिम निष्कर्ष अभी सामने आना बाकी है। इसका अर्थ यह है कि जांच प्रक्रिया अभी जारी है और विशेषज्ञ संस्थाएं दुर्घटना के कारणों का विस्तृत विश्लेषण कर रही हैं। इस स्थिति में अदालत द्वारा हस्तक्षेप करना जांच प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है, जो उचित नहीं होगा।

गौरतलब है कि पिछले वर्ष 12 जून को एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171, जो अहमदाबाद से लंदन के गैटविक हवाई अड्डे के लिए रवाना हुई थी, टेकऑफ के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। यह दुर्घटना सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा से उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद हुई, जब विमान एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल परिसर में जा गिरा और उसमें भीषण आग लग गई। इस हादसे में विमान में सवार 242 लोगों में से 241 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि जमीन पर मौजूद 19 अन्य लोगों ने भी अपनी जान गंवाई। यह दुर्घटना देश के विमानन इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक बन गई। इस हादसे के बाद विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने जांच शुरू की और प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट का उद्देश्य दुर्घटना के संभावित कारणों की शुरुआती जानकारी प्रदान करना था, जबकि अंतिम रिपोर्ट विस्तृत जांच के बाद जारी की जाएगी। विमान दुर्घटनाओं की जांच एक अत्यंत जटिल और तकनीकी प्रक्रिया होती है, जिसमें कई विशेषज्ञ और वैज्ञानिक शामिल होते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट का यह फैसला न्यायपालिका और विशेषज्ञ संस्थाओं के बीच संतुलन बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस निर्णय ने यह स्पष्ट किया है कि न्यायपालिका का उद्देश्य न्याय सुनिश्चित करना है, लेकिन वह विशेषज्ञता से जुड़े मामलों में विशेषज्ञ संस्थाओं के कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करती। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका संस्थागत जिम्मेदारियों और अधिकार क्षेत्रों का सम्मान करती है। यह फैसला उन सभी मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है, जहां तकनीकी और विशेषज्ञता से जुड़े मुद्दों पर न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की जाती है।

संपादकीय

डिजिटल खतरे को भी आतंकवाद माना

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और इंटरनेट के दौर में लगातार घातक और ग्लोबल होते आतंकवाद से निपटना देश-दुनिया की बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। आधुनिक तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के चलते दुनिया का कोई कोना आज आतंकवाद से अछूता नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आतंकवाद से मुकाबला करने वाला हमारा तंत्र तकनीक और संसाधनों के दृष्टिकोण से उन्नत नहीं है, जिसके चलते अपराधी पुलिस व सुरक्षा बलों पर इक्कीस पड़ते हैं। संगठित अपराधी गिरोह हवाला और अन्य स्रोतों से वित्तीय संसाधन जुटाकर सरकारों को चुनौती देने लगे हैं। इस संकट के आलोक में भारत सरकार ने आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करने की रणनीति को अंतिम रूप दिया है। भारत सरकार ने अब आतंकवाद के खिलाफ जंग में नई राष्ट्रीय नीति और रणनीति 'प्रहार' को सिरे चढ़ाने की घोषणा की है। 'प्रहार' अर्थात् 'प्रिवेंशन, रिस्पांस एंड हेल्थिंग अप्रोच टू एंटी-टेररिज्म।' गृह मंत्रालय द्वारा तैयार इस आतंकवाद-रोधी नीति और रणनीति में पहली बार डिजिटल खतरों को आतंकवाद की श्रेणी में रखा गया है। हाल ही के दिनों में देश के भोले-भाले नागरिकों को जिस तरह हाउस अरेस्ट करके सरेआम लूटा गया, उससे देश के सभ्य समाज में भय व्याप्त है। लोगों की जीवनभर की जमापूंजी और सेवानिवृत्ति लोगों के पूरे सेवाकाल की बचत पर जिस तरह ऑनलाइन डाका डाला जा रहा है, उसे देखते हुए डिजिटल खतरों को आतंकवाद की श्रेणी में रखना वक्त की जरूरत है। साथ ही यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि डिजिटल अपराधों से आतंक फैलाने वालों को आतंकवादियों जैसी सजा देने का प्रावधान हो। हाल ही के दिनों में देश में साइबर हमले और आपराधिक हैकिंग के मामले भी खासे बढ़े हैं। यह स्वागतयोग्य है कि नई आतंकवाद विरोधी नीति में दुनिया के काले कारोबार की कुख्यात धारा डार्क वेब, क्रिप्टो मायाजाल आदि उन्नत तकनीकों द्वारा अपराध जगत को सींचने वाले वित्तपोषक तंत्र से निपटना भी नई आतंकवाद विरोधी नीति का लक्ष्य होगा, जो आज देश में आतंकवाद पोषण का जरिया बन रहा है।

निस्संदेह, हाल ही के दिनों में सीमा पार से जारी ड्रोन हमले और साइबर आतंकवाद देश की सुरक्षा के लिए चुनौती बनता जा रहा है। ऐसे में नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए आतंकवादी हमलों पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी है। यदि खतरे को समय रहते भांपते हुए तत्काल प्रतिक्रिया दी जा सके तो नागरिकों के हित सुरक्षित रह सकते हैं। इसके लिये जरूरी है कि नागरिक सुरक्षा में लगी पुलिस, सुरक्षा बलों तथा अन्य आंतरिक क्षमताओं को एकीकृत किया जाए। साथ ही वैश्विक स्तर पर भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाले संगठनों पर नकेल कसने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय की जरूरत है। आतंकवाद के खिलाफ जारी इस रणनीति में आतंकी हमलों की रोकथाम के लिए इंटेलिजेंस सूचनाओं की गुणवत्ता बढ़ाने, सुरक्षा बलों को उन्नत हथियार उपलब्ध कराने, नई तकनीक से लैस करने, पुलिस, एनएसजी व केंद्रीय सुरक्षा बलों में समन्वय से तत्काल प्रतिक्रिया देने, सुरक्षा एजेंसियों के आधुनिकीकरण व प्रशिक्षण से आतंक पर प्रहार की क्षमता को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पहली बार भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को भी आतंकवाद रोधी कानूनी ढांचे में शामिल किया गया है। इसके अलावा समाज में कट्टरपंथ को रोकने के लिए किए जाने वाले प्रयासों का जिक्र आतंकवाद विरोधी नीति में शामिल है, जिसमें सामुदायिक नेताओं, धर्मगुरु व स्वयंसेवी संगठनों की मदद भी ली जाएगी। निस्संदेह, समय के साथ बढ़ती आतंकवाद की चुनौती के मुकाबले में नागरिकों की सजगता व सतर्कता एक बड़ी भूमिका हो सकती है। वहीं दूसरी ओर नई आतंकवाद विरोधी नीति में समग्र सामाजिक प्रयासों का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें आतंकी हमलों के बाद समुदाय को एकीकृत करने, मनोवैज्ञानिकों, अधिवक्ताओं तथा समाजसेवी संगठनों की मदद से स्थिति सामान्य करने में लोगों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। लेकिन यहां यह भी जरूरी है कि आतंकवाद के खतरों को कम करने के लिए मानवाधिकार और कानून व्यवस्था पर आधारित प्रतिक्रिया दी जाए। निस्संदेह, लगातार मारक होती आतंकवाद की चुनौती के मुकाबले के लिए समग्र नीति के साथ नागरिकों की सजगता व सतर्कता भी बेहद जरूरी है।

खेल भावना के अनुरूप नहीं है यह व्यवहार

> "किसी स्थापित परंपरा को तजना हैरानीजनक है और खेल शिष्टाचार की कमी दिखाता है। जब पाकिस्तान के खिलाफ खेलने, साथ में कमेंट्री करने, प्रसारकों और टीमों को पैसा कमाने में मदद करने में कोई आपत्ति नहीं है तो मैदान पर आधिकारिक हाथ मिलाने में क्या हर्ज है।

आखिर में, शेक्सपियर के शब्दों में 'यह एक मूर्ख द्वारा सुनाई कहानी जैसा रहा, हो-हल्ले और आवेश से भरी, पर सिर-पैर कोई नहीं'। बैट और बॉल के बीच मुकाबले के रूप में चलाई गई गोलियों की इस लड़ाई में, किसी को अंदाज़ा नहीं कि खेल का अंतिम परिणाम क्या होगा, सिवाय उन लोगों के लालच को संतुष्ट करने के, जिन्हें कैश काउंटिंग मशीन की सरसराहट भरी आवाज़ पसंद है।

दंभ भरे दिमागों के टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ने और मैच कराने के लिए खर्च की गई ऊर्जा आखिकार क्या इसी लायक थी? एक समय था जब भारत-पाकिस्तान मैच, भले ही मुकाबला ज्यादातर रोमांचक न भी हो, दोनों तरफ के खिलाड़ियों के ज़बरदस्त खेल कौशल का नमूना हुआ करता था। क्रिकेट के नज़रिए से, यह देखना दुखद है कि एक समय काफी मज़बूत रहा पाकिस्तान अब घबराए हुए, अनाड़ी खिलाड़ियों की टीम सरीखा है, खिंचाई करने वाले अपने से बड़े बच्चों की टोली में फंसे एक सहमे बालक की तरह।

आश्चर्य और रोमांचक संभावनाओं से भरपूर विश्व कप, जो कट्टर परंपरावादियों तक को क्रिकेट के टी-20 प्रारूप के प्रति अपनी नापसंदगी पर फिर से सोचने पर मजबूर कर दे, भारत-पाकिस्तान का मैदान से इतर चला नाटक इस बात की बेतरह याद दिलाता है कि खेल का राजनीति के साथ घालमेल क्यों नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार, नए छोटे देशों ने क्रिकेट के इस प्रारूप को अपनाया है और पुरानी टीमों को भी चुनौती दे रहे हैं, उससे टेस्ट क्रिकेट के अवसान को लेकर बना डर और पक्का हो चला है। जब नेपाल इंग्लैंड को लगभग हरा सकता है, यूनाइटेड स्टेट्स की टीम भारत के धमाकेदार बैटिंग को लगभग नाकाम कर डाले और ज़िम्बाब्वे बड़ी जीत

हासिल कर सकता है, तो यह साफ़ है कि टी-20 की दुनिया में कोई भी अजेय दिग्गज नहीं है। टेस्ट मैच प्रारूप खेलने वाले देशों का कुलीन क्लब लंबे समय तक ऐसे देशों की तलाश करता रहा, जिनसे सदस्यों की सीमित संख्या बढ़ सकें, लेकिन कोई फायदा नहीं। इसके विस्तार में नाकामी, अन्य कई कारणों के अलावा, इसके लिए आवश्यक मुश्किल कौशल पास न होना भी हो सकते हैं, जिनमें महारत हासिल करने में समय और एक माकूल क्रिकेट संस्कृति खपती है।

1970 के दशक के बाद से यह माना जाता था कि जहां टेस्ट क्रिकेट नाकाम रहा, वहां 50 ओवर का खेल कामयाब होगा। हालांकि इसने सदस्यता का अंतर कम किया और 'औसत दर्जे की' टीमों को मुकाबला करने का मौका दिया, लेकिन इसमें भी खेल का मुख्य प्रारूप लगभग टेस्ट क्रिकेट जैसा ही रहा, अफगानिस्तान एक दुर्लभ अपवाद है। लेकिन टी-20 ने सचमुच न सिर्फ क्रिकेट खेलने के तरीके में क्रांति ला दी है, बल्कि उन देशों की कल्पना को भी जगाया है जो थकाऊ और ऊर्जा खपाऊ टेस्ट क्रिकेट में रणनीतिक कौशल में पिछड़ने पर हार की शर्मिंदगी से बचना चाहते थे।

हमारे मौजूदा समय के लिए एक उक्ति जो एकदम सही बैठती है : 'जल्दबाज़ी एक खूबी है; सब्र एक बुराई'। क्रीज पर धैर्य और कुशलतापूर्ण एकाग्र नज़र, बैटिंग के दो ऐसे आधार स्तंभ, जिनसे एक पारंपरिक टेस्ट बल्लेबाज सफल होता है। उसे अपने जल्दबाज़ी पर काबू पाने, सही समय का इंतजार करना और राजमिस्त्री की तरह ईंट-दर-ईंट पारी का निर्माण बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसे दरवाज़े की नॉब ठीक करने की बजाय एक पूरा महल उसारना होता है।

जबकि टी-20 क्रिकेट में बल्लेबाजी एक रेसिंग ट्रैक है, जिस पर चलाने को चालक को गियर-विहीन कार दी जाती है। कोई सड़क कहीं भी ऊबड़-खाबड़ नहीं होती, निबटने को कोई खतरा नहीं । उसके पास रोमांच पैदा करने और जीत हासिल करने का लाइसेंस है। इसके लिए बेहतर छवि होगी मशीन गन या उससे भी घातक हथियार पकड़े हुए एक बंदा जो तूफान की भांति तड़ातड़ गोलियां बरसा रहा है। यह ज्वालामुखी विस्फोट जैसा है, जिसने बहुत सारे 'साहसी युवाओं' को सम्मोहित कर रखा है और 'बोर' हुए बड़ों तक को अपनी लत में फांस लिया है।

पांच दिन चलने वाला खेल सिमटकर सिर्फ़ साढ़े तीन घंटे का खेल रह गया है, इसने क्रिकेट के व्याकरण को उलट दिया है। 360 डिग्री घूमने वाले बैट, गायब होते डिफेंसिव प्रोड्स, स्कूप और रिवर्स स्वीप, रैंप अप, जानबूझकर बैट के किनारे से मारे गए शॉट जो बाउंड्री की ओर बिजली की तरह लपकते हैं। यह एक तबाही बरपाने जैसा है और इस बौछार का मुकाबला करने के लिए बॉलर भी धोखा और चकमा देने के नए-नए तरीके ईजाद कर रहे हैं। फिंगर फ्लिक, नकल बॉल्स, साइड-ऑन रिलीज़, सटल पॉज़ और अनेकानेक किस्म की स्पीड वेरिएशन उन कई तरीकों में हैं, जिनका इस्तेमाल बैट्समैन को बांधकर रखने की उम्मीद में किया जा रहा है। टिके रहने लिए गेंदबाज को जादूगर बनना होता है वरना जल्द ही हार का सामना करना पड़ेगा।

जब क्रिकेट पागलपन वाली रफ्तार से खेला जा रहा हो और दुनिया इसे अपना रही है, तो क्या भारत और पाकिस्तान के लिए मैदान पर अपना कोई अजीब ड्रामा करना ज़रूरी था? मैं सूर्यकुमार यादव का, बतौर एक बैट्समैन और उनके चेहरे की भंगिमाओं की कला का कायल हूं, जो किसी मंजे हुए अभिनेता तक को मात देती हैं, वे अपना चेहरा सिकोड़ते और फैलाते हैं, अपना माथा सपाट करते हैं, कभी-कभी अपनी जीभ भी निकालते हैं और आंखें बाहर निकालकर भावनाओं का प्रदर्शन करते हैं।

गुणों से परिपूर्ण भारतीय कप्तान को यह शोभा नहीं देता कि वह ऐसा व्यवहार दिखाए और अपने विरोधी कप्तान से हाथ मिलाने से मना कर दे। एक स्थापित परंपरा को तजना हैरान-परेशान करने वाला है और खेल शिष्टाचार की पूर्णरूपेण कमी दिखाता है। भारत कुछ महीने पहले खेले गए एशिया कप में तीन मैचों के दौरान की गई अपनी हरकत को दोहराकर क्या साबित करना चाहता है?

जहां एक ओर यादव ने शायद किसी के निर्देशों पर, टॉस के दौरान पाकिस्तान के कप्तान से सीधी नज़र नहीं मिलाईं और हाथ मिलाने की रस्म के लिए टीमें लाइन में नहीं लगीं, वहीं दूसरी ओर भारत के पूर्व कप्तान और खेल के प्रतीक रहे रोहित शर्मा को पाकिस्तान के किंवदंती बने पूर्व खिलाड़ी वसीम अकरम को गले लगाते हुए कैमरों ने कैद कर लिया। यह दो इंसानों का एक-दूसरे को शुभकामना देने का एक मिसाल था।

हमें आपके खिलाफ खेलने में कोई दिक्कत नहीं, हमें भारत और पाकिस्तान के पुराने धुरंधरों के साथ कमेंट्री करने, एक-दूसरे के चुटकुलों पर हंसने और मुस्कुराने, ब्रॉडकास्टर्स की मदद करने और दोनों टीमों द्वारा पैसे कमाने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कृपया, मैदान पर आधिकारिक रूप से हाथ न मिलाएं। दोगलेपन की न तो कोई हद होती है, न ही कोई बाउंडरी।

प्रेरणा

विनम्रता का अदृश्य द्वार: जब झुकने से आत्मा ईश्वर से मिलती है

एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर काली मंदिर में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में उपस्थित थे। मंदिर का वातावरण भक्ति से भरा हुआ था। घंटियों की ध्वनि, मंत्रों का कंपन, और श्रद्धालुओं की आस्था से पूरा परिसर एक दिव्य ऊर्जा से स्पंदित हो रहा था। पूजा सम्पन्न हुई, भोग वितरित हुआ, और धीरे-धीरे सभी श्रद्धालु अपने घरों को लौटने लगे। कुछ ही समय में मंदिर का प्रांगण शांत हो गया। जहां कुछ देर पहले भीड़ थी, वहां अब केवल मौन था। उसी मौन में एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा था, जिसे केवल एक जाग्रत आत्मा ही समझ सकती थी।

जब सब लोग जा चुके थे, तब स्वामी जी अपने स्थान से उठे और उन जूठी पत्तलों को उठाने लगे, जिन पर श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया था। यह दृश्य देखने में साधारण था, लेकिन उसके पीछे जो भाव था, वह अत्यंत असाधारण था। यह केवल सफाई का कार्य नहीं था, बल्कि आत्मा की एक गहरी साधना थी। उसी समय मंदिर के पुजारी की नजर उन पर पड़ी। वह आश्चर्यचकित रह गया। वह तुरंत उनके पास आया और विनम्रता से बोला कि यह कार्य उनके योग्य नहीं है। उसने कहा कि इसके लिए सेवक हैं, और एक महान संत को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए।

स्वामी जी ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, शांति थी, और एक ऐसी गहराई थी, जिसमें सत्य का प्रकाश झलकता था। उन्होंने शांत स्वर में कहा कि वह इन पत्तलों को उठाकर अपने भीतर के अहंकार को बाहर निकाल रहे हैं। यह उत्तर केवल शब्द नहीं था, बल्कि एक ऐसा अनुभव था, जो केवल वही समझ सकता है, जिसने अपने भीतर की यात्रा शुरू की हो।

अहंकार मनुष्य के भीतर सबसे सूक्ष्म और सबसे गहरी बाधा है। यह वह परदा है, जो मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से दूर रखता है। जब मनुष्य अपने ज्ञान, अपने पद, अपनी प्रतिष्ठा या अपनी शक्ति के कारण स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगता है, तब यह अहंकार धीरे-धीरे उसके भीतर जड़ें जमा लेता है। यह उसे यह विश्वास दिलाता है कि वह अलग है, कि वह विशेष है। लेकिन यही अहंकार उसे ईश्वर से दूर कर देता है।

ईश्वर तक पहुंचने के लिए मनुष्य को स्वयं को खाली करना पड़ता है। जब तक मनुष्य अपने भीतर अहंकार को पकड़े रहता है, तब तक उसके भीतर ईश्वर के लिए स्थान नहीं बनता। विनम्रता वह प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपने भीतर की अनावश्यक पहचान को छोड़ता है। यह उसे उसके वास्तविक स्वरूप के निकट ले जाती है।

जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस उन पत्तलों को उठा रहे थे, तब वह केवल एक कार्य नहीं कर रहे थे, बल्कि वह अपने भीतर उस सूक्ष्म अहंकार को पहचान रहे थे, जो हर मनुष्य के भीतर कहीं न कहीं मौजूद होता है। यह अहंकार कभी-कभी बहुत सूक्ष्म होता है। यह सेवा के रूप में भी छिप सकता है, यह ज्ञान के रूप में भी छिप सकता है। लेकिन जब मनुष्य सचेत होता है, तब वह इसे पहचान सकता है और उससे मुक्त हो सकता है।

विनम्रता का अर्थ स्वयं को छोटा बनाना नहीं है, बल्कि स्वयं को सत्य के निकट लाना है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह इस विशाल सृष्टि का केवल एक छोटा सा अंश है, तब उसके भीतर स्वाभाविक रूप से विनम्रता उत्पन्न होती है। यह विनम्रता उसे दूसरों से जोड़ती है। यह उसे यह अनुभव कराती है कि वह अलग नहीं है, बल्कि वह उसी चेतना का हिस्सा है, जिससे यह सम्पूर्ण सृष्टि बनी है।

अहंकार हमेशा अलगाव पैदा करता है। यह मनुष्य को दूसरों से दूर करता है। यह उसे अकेला बना देता है। लेकिन विनम्रता एकता पैदा करती है। यह मनुष्य को दूसरों के निकट लाती है। यह उसे प्रेम से जोड़ती है।

जब मनुष्य विनम्र होता है, तब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वह जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगता है। वह हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश देखने लगता है। वह हर अनुभव को एक शिक्षा के रूप में स्वीकार करता है। यह स्वीकार्यता उसे भीतर से शांत करती है।

विनम्रता मनुष्य को स्वतंत्र बनाती है। जब अहंकार समाप्त होता है, तब मनुष्य को स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। उसे दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। वह स्वयं में पूर्ण हो जाता है।

स्वामी जी का यह कार्य हमें यह सिखाता है कि आध्यात्मिकता केवल ध्यान या पूजा तक सीमित नहीं है। यह जीवन के हर छोटे कार्य में प्रकट होती है। जब मनुष्य बिना किसी अपेक्षा के सेवा करता है, तब वह ईश्वर के सबसे निकट होता है।

झुकना कमजोरी का संकेत नहीं है। झुकना शक्ति का संकेत है। क्योंकि केवल वही झुक सकता है, जो भीतर से मजबूत होता है। जो भीतर से कमजोर होता है, वह हमेशा स्वयं को ऊंचा दिखाने की कोशिश करता है।

जब मनुष्य झुकता है, तब वह सीखने के लिए तैयार होता है। और जब वह सीखने के लिए तैयार होता है, तब वह विकसित होने लगता है। धीरे-धीरे वह यह समझने लगता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। वह समझने लगता है कि जीवन केवल स्वयं के लिए नहीं है, बल्कि एक उच्चतर उद्देश्य के लिए है।

और उसी क्षण, जब वह स्वयं को भूल जाता है, जब वह अपने अहंकार को छोड़ देता है, तब उसके भीतर ईश्वर प्रकट होते हैं।

तब उसे यह अनुभव होता है कि ईश्वर कहीं दूर नहीं हैं। वे उसी क्षण उसके भीतर उपस्थित हो जाते हैं, जब उसका अहंकार समाप्त होता है। विनम्रता ही वह द्वार है, जिससे होकर आत्मा ईश्वर तक पहुंचती है।

और जब यह द्वार खुलता है, तब मनुष्य केवल मनुष्य नहीं रहता, वह स्वयं ईश्वर की अभिव्यक्ति बन जाता है।

मुफ्त रेवड़ी संस्कृति जीवंत लोकतंत्र के लिये घातक

भारतीय लोकतंत्र की विडंबना यह है कि चुनाव आते ही जनसेवा का स्वरूप बदलकर जनलुभावन राजनीति में परिवर्तित हो जाता है। राजनीतिक दलों ने मुफ्त की योजनाओं को चुनावी सफलता का शॉर्टकट बना लिया है। मतदाताओं को तात्कालिक आर्थिक लाभ देकर वोट हासिल करने की प्रवृत्ति लगातार मजबूत हो रही है। आगामी तीन-चार माह में विधानसभा चुनाव होने है, इसी संदर्भ में जब असम, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हुईं, तब इस संस्कृति का प्रभाव और स्पष्ट दिखाई देने लगा। इसी पृष्ठभूमि में देश की शीर्ष अदालत, सर्वोच्च न्यायालय, ने मुफ्त की योजनाओं के अनियंत्रित विस्तार पर गंभीर टिप्पणी की। यह टिप्पणी केवल कानूनी दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा को लेकर एक चेतावनी है।लोकतंत्र का मूल उद्देश्य जनकल्याण है। राज्य का दायित्व है कि वह गरीब, वंचित और कमजोर वर्गों को सहारा दे। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं, न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी-ये सब कल्याणकारी राज्य की पहचान हैं। लेकिन जब जनहित और चुनावी लाभ के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, तब समस्या जन्म लेती है। लक्षित समर्थन और अतिरेक उदारता में अंतर है। एक ओर ऐसी योजनाएं हैं जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती हैं, दूसरी ओर ऐसी घोषणाएं हैं जो केवल मतदाता को तात्कालिक राहत देकर उसे निर्भरता की आदत सिखाती हैं। जब राजस्व घाटे से जूझ रहे राज्य मुफ्त बिजली, मुफ्त यात्रा या नकद वितरण की घोषणाएं करते हैं, तो प्रश्न उठता है कि यह संसाधन कहां से आएंगे और इसकी कीमत कौन चुकाएगा? राजकोषीय अनुशासन किसी भी राज्य की आर्थिक सेहत का आधार है। यदि राज्य अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिए खजाने को खाली करता है, तो दीर्घकालिक विकास प्रभावित होता है। जो धन बुनियादी ढांचे के निर्माण, अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण, विद्यालयों की गुणवत्ता सुधार और रोजगार सृजन में लगना चाहिए, वह वोटों की फसल काटने में खर्च हो जाता है। यह प्रवृत्ति केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि नैतिक दृष्टि से भी चिंताजनक है। लोकतंत्र में मतदाता की स्वतंत्रता सर्वोपरि मानी जाती है। यदि मतदाता को परोक्ष रूप से आर्थिक प्रलोभन देकर प्रभावित किया जाता है, तो यह स्वतंत्र निर्णय की भावना को कमजोर करता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने तार्किक प्रश्न उठाया कि राज्य रोजगार सृजन और कौशल विकास पर अधिक ध्यान क्यों नहीं देते? वास्तव में रोजगार ही स्थायी सशक्तीकरण का माध्यम है। जब व्यक्ति अपने श्रम और कौशल से आय अर्जित करता है, तब उसमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दोनों विकसित होते हैं। इसके विपरीत, निरंतर मुफ्त सुविधाएं व्यक्ति को निर्भर बनाती हैं। धीरे-धीरे परिश्रम की संस्कृति कमजोर पड़ती है और समाज में अकर्मण्यता की मानसिकता पनपने लगती है। यह स्थिति लोकतंत्र की सुदृढ़ता के लिए खतरनाक है, क्योंकि लोकतंत्र केवल वोट डालने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि सक्रिय और जिम्मेदार नागरिकता का नाम है। चुनाव पूर्व घोषित योजनाओं की निष्पक्षता भी प्रश्नों के घेरे में है। जब आचार संहिता लागू रहने के दौरान बड़े पैमाने पर आर्थिक वितरण होता है, तो विपक्षी दल इसे असमान प्रतिस्पर्धा मानते हैं। ऐसे मामलों में निष्पक्ष निगरानी की जिम्मेदारी भारत का निर्वाचन आयोग पर आती है। निर्वाचन आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी दल मतदाताओं को अप्रत्यक्ष रिश्वत देकर चुनावी लाभ न ले। आचार संहिता का उल्लंघन केवल तकनीकी त्रुटि नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादा का हनन है। यदि इस पर कठोर कार्रवाई नहीं होती, तो भविष्य में यह प्रवृत्ति और गहरी जड़ें जमा सकती है। निस्संदेह, इस बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती है कि राज्यों का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वे विशेष रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की खास तौर से देखभाल करें। हालांकि, जब राजस्व घाटे वाले राज्य मुफ्त की योजनाओं पर बड़ी रकम खर्च करते हैं, तो सरकारी खजाने पर दबाव और अधिक बढ़ जाता है। विडंबना यह है कि जिस धनराशि का इस्तेमाल बुनियादी ढांचे में सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं को सक्षम बनाने और शिक्षा की सुविधा को समृद्ध करने के लिये किया जाना चाहिए, वो राशि अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिये खर्च कर दी जाती है। जरूरत इस बात की है कि कौशल विकास के जरिये लोगों को इस तरह सक्षम बनाया जाए जिससे उन्हें दीर्घकालिक व स्थायी लाभ मिल सकें। यह भी समझना होगा कि मुफ्त योजनाओं का हर स्वरूप गलत नहीं है। आपातकालीन परिस्थितियों में राहत देना, महामारी या प्राकृतिक आपदा के समय सहायता पहुंचाना, सामाजिक न्याय के तहत वंचित वर्गों को अवसर देना-ये सब राज्य की जिम्मेदारी है। परंतु चुनावी मौसम में अचानक घोषणाओं की बाढ़ आ जाना और दीर्घकालिक वित्तीय परिणामों की अनदेखी करना लोकतांत्रिक परिपक्वता का संकेत नहीं है। यह राजनीतिक दलों के वैचारिक दिवालियेपन को दर्शाता है, जहां दूरदृष्टि की जगह तात्कालिक लाभ को प्राथमिकता दी जाती है। लोकतंत्र की मजबूती केवल संस्थाओं से नहीं, बल्कि नागरिकों की सजगता से भी आती है। यदि मतदाता केवल तात्कालिक लाभ देखकर मतदान करता है, तो वह अनजाने में ऐसी संस्कृति को प्रोत्साहित करता है जो अंततः उसी के भविष्य को प्रभावित करती है। परिपक्व मतदाता वही है जो घोषणाओं के पीछे की मंशा और आर्थिक व्यवहार्यता को समझे। वह यह पूछे कि पांच साल बाद राज्य की आर्थिक स्थिति क्या होगी, विकास की दिशा क्या होगी और रोजगार के अवसर कितने बढ़ेंगे। लोकतंत्र में वोट केवल अधिकार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है। आज भारत स्वयं को वैश्विक मंच पर एक सशक्त लोकतंत्र के रूप में स्थापित करना चाहता है। हम विश्वगुरु बनने का संकल्प लेते हैं, लेकिन यदि हमारी राजनीति लोकलुभावनवाद के जाल में उलझी रहेगी, तो यह संकल्प खोखला सिद्ध होगा। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गौरव तभी सार्थक है जब हमारी नीतियां दूरदर्शी, संतुलित और टिकाऊ हों।

अभियान

फाल्गुन मास का ब्रह्मांडीय रहस्य: चंद्र चेतना, तांत्रिक ऊर्जा और मानव आत्मा का अदृश्य संवाद

सनातन धर्म में समय केवल तिथियों का क्रम नहीं है, बल्कि वह चेतना की लय है। हिंदू पंचांग की रचना किसी साधारण गणना का परिणाम नहीं, बल्कि ब्रह्मांड और मानव जीवन के सूक्ष्म संबंध का जीवंत विज्ञान है। यहाँ महीनों का निर्धारण सूर्य की स्थिरता से नहीं, बल्कि चंद्रमा की गतिशीलता से होता है। प्रत्येक महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा जिस नक्षत्र में स्थित होता है, उसी नक्षत्र के आधार पर उस महीने का नाम रखा जाता है। जब पूर्णिमा के दिन चंद्रमा फाल्गुनी नक्षत्र में विराजमान होता है, तब उस कालखंड को फाल्गुन कहा जाता है। यह केवल एक नामकरण नहीं, बल्कि एक ऊर्जा-चिन्ह है, जो बताता है कि इस समय ब्रह्मांड की कौन-सी तरंगें पृथ्वी और मानव मन पर सबसे अधिक सक्रिय होती हैं।

चंद्रमा को वैदिक ज्योतिष में मन, भावना और अवचेतन का अधिपति माना गया है। सूर्य आत्मा का प्रतीक है, परंतु मन वह माध्यम है जिसके द्वारा आत्मा संसार का अनुभव करती है। यदि मन अस्थिर है तो जीवन अशांत होता है, और यदि मन संतुलित है तो परिस्थितियाँ कठिन होने पर भी व्यक्ति भीतर से स्थिर रहता है। फाल्गुन का महीना इसी मन के संतुलन और शुद्धि का काल है। यह वह समय है जब चंद्र ऊर्जा अपने चरम पर होती है और मानव चेतना अधिक संवेदनशील हो जाती है। प्राचीन ग्रंथ पद्मपुराण में उल्लेख मिलता है कि यह काल चंद्र ऊर्जा के विशेष जागरण का समय है। इसका अर्थ केवल खगोलीय स्थिति नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि इस अवधि में मन की सुप्त परतें सक्रिय हो सकती हैं। जब पूर्णिमा आती है तो चंद्रमा पूर्ण प्रकाश में होता है। उसी प्रकार जब व्यक्ति इस काल में साधना करता है, तो उसके भीतर भी एक आंतरिक पूर्णिमा घटित हो सकती है। मन के अंधकार में छिपे संशय, भय और भ्रम इस प्रकाश में स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं।

तांत्रिक दृष्टि से फाल्गुन का महीना अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। तंत्र में चंद्रमा को मानसिक शक्ति का स्रोत माना जाता है। सूर्य तप का प्रतीक है, परंतु चंद्रमा रस और ऊर्जा का प्रतीक है। जब चंद्रमा पूर्ण होता है, तब तांत्रिक साधक इसे चेतना के द्वार के रूप में देखते हैं। उनका विश्वास है कि पूर्णिमा की रात्रि में ब्रह्मांड और साधक के बीच की दूरी कम हो जाती है। इस समय की साधना गहन परिणाम दे सकती है, क्योंकि मन अधिक ग्रहणशील होता है।

फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी रात्रि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस तिथि पर चंद्रमा सूर्य के अत्यंत निकट होता है। यह स्थिति प्रतीकात्मक रूप से मन और आत्मा के मिलन का संकेत देती है। जब मन आत्मा के निकट होता है, तब व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप का आभास होता है। इसी कारण इस रात्रि को भगवान शिव की आराधना की जाती है। शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि वह शून्यता और चेतना का बोध हैं। जब मन शांत होकर शून्य में स्थिर होता है, तभी शिव तत्व का अनुभव होता है।

फाल्गुन का महीना केवल धार्मिक अनुष्ठानों का समय नहीं, बल्कि यह प्रकृति के रूपांतरण का भी काल है। शीत ऋतु का अंत और वसंत का आगमन इसी समय होता है। वृक्षों पर नई कोंपलें आती हैं, वातावरण में सुगंध भर जाती है, और प्रकृति एक नई ऊर्जा से स्पंदित होती है। यह बाहरी परिवर्तन वास्तव में आंतरिक परिवर्तन का प्रतीक है। जैसे प्रकृति पुराने पत्तों को त्यागकर नवीनता को स्वीकार करती है, वैसे ही मनुष्य भी अपने पुराने विचारों, दुखों और सीमाओं को त्याग सकता है।

इस महीने में चंद्रदेव को अर्घ्य देने की परंपरा अत्यंत अर्थपूर्ण है। दुग्ध मिश्रित जल से अर्घ्य देना केवल श्रद्धा का प्रतीक नहीं, बल्कि यह मन की शुद्धि का संकेत है। दूध शुद्धता और पोषण का प्रतीक है, जबकि जल प्रवाह और लचीलापन दर्शाता है। जब इन दोनों को मिलाकर चंद्रमा को अर्पित किया जाता है, तो यह मन के संतुलन और भावनात्मक शांति की साधना बन जाता है। व्यक्ति जब नियमित रूप से ऐसा करता है, तो उसके भीतर का तनाव धीरे-धीरे कम होने लगता है।

फाल्गुन में भगवान श्रीकृष्ण की आराधना का भी विशेष महत्व है। श्रीकृष्ण प्रेम, माधुर्य और चेतना के प्रतीक हैं। फाल्गुन का रंग, उसका उल्लास, और उसका रसमय वातावरण कृष्ण तत्व से गहराई से जुड़ा हुआ है। जब व्यक्ति प्रेम की भावना में स्थित होता है, तब उसका मन शुद्ध होता है। प्रेम मन को विस्तार देता है, और विस्तार में ही ईश्वर का अनुभव संभव है। इसी प्रकार माता लक्ष्मी की पूजा इस महीने में समृद्धि और संतुलन का प्रतीक मानी जाती है। लक्ष्मी केवल धन की अधिष्ठात्री नहीं, बल्कि वह सामंजस्य और सौंदर्य की ऊर्जा हैं। जब मन संतुलित होता है, तब जीवन में सौंदर्य स्वतः प्रकट होता है।

फाल्गुन का संबंध दान और तर्पण से भी है। इस समय दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। दान केवल वस्तु का त्याग नहीं, बल्कि अहंकार का त्याग है। जब व्यक्ति कुछ देता है, तो वह अपने भीतर की संकीर्णता को छोड़ता है। तर्पण पितरों के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। जब व्यक्ति कृतज्ञ होता है, तो उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। कृतज्ञता मन को विनम्र बनाती है और विनम्र मन ही ईश्वर के अनुभव के योग्य होता है।

चंद्रमा का प्रभाव केवल मनुष्य तक सीमित नहीं है। समुद्र की ज्वार-भाटा से लेकर पौधों की वृद्धि तक, सब कुछ चंद्र ऊर्जा से प्रभावित होता है। जब पूर्णिमा होती है, तब जल तत्व अधिक सक्रिय होता है। मानव शरीर में भी जल तत्व की प्रधानता है। इसीलिए पूर्णिमा का प्रभाव मन पर अधिक पड़ता है। यदि व्यक्ति सजग हो, तो वह इस ऊर्जा का उपयोग अपने आत्मिक विकास के लिए कर सकता है।

फाल्गुन का वास्तविक संदेश यह है कि मन और आत्मा का संतुलन ही जीवन का आधार है। यदि मन असंतुलित है, तो बाहरी सफलता भी सुख नहीं दे सकती। और यदि मन शांत है, तो साधारण जीवन भी आनंदमय हो सकता है। यह महीना व्यक्ति को अवसर देता है कि वह अपने भीतर झांके, अपने विचारों को देखे, अपनी भावनाओं को समझे और उन्हें संतुलित करे।

जब व्यक्ति इस काल में ध्यान, जप और साधना करता है, तो उसके भीतर की सुप्त शक्तियाँ जाग्रत हो सकती हैं। यह जागरण अचानक नहीं होता, बल्कि धीरे-धीरे होता है। जैसे चंद्रमा अमावस्या से पूर्णिमा तक यात्रा करता है, वैसे ही चेतना भी अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ती है। यह यात्रा ही जीवन का सार है।

फाल्गुन अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। यह वह समय है जब मनुष्य अपने भीतर की पूर्णिमा को पहचान सकता है। जब वह अपने भीतर के चंद्र को समझ लेता है, तब वह अपने भीतर के सूर्य को भी पहचान लेता है। मन और आत्मा का यह मिलन ही सच्चा योग है। यही वह क्षण है जब व्यक्ति अनुभव करता है कि वह ब्रह्मांड से अलग नहीं, बल्कि उसी का अंश है। और यही फाल्गुन मास का गहन, दिव्य और अदृश्य रहस्य है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

लोकतंत्र की मर्यादा और संवैधानिक जिम्मेदारी का संदेश

(जीएनएस)। भारत जैसे विविधताओं से भरे राष्ट्र में लोकतंत्र केवल चुनावों और शासन की प्रक्रिया का नाम नहीं है, बल्कि यह समाज के हर वर्ग, हर समुदाय और हर नागरिक के बीच आपसी सम्मान, विश्वास और भाईचारे की भावना पर आधारित एक जीवंत व्यवस्था है। इस व्यवस्था की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि समाज के प्रभावशाली और जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग किस प्रकार अपने शब्दों, अपने व्यवहार और अपने निर्णयों के माध्यम से सामाजिक संतुलन बनाए रखते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई एक महत्वपूर्ण टिप्पणी ने इसी मूल भावना को पुनः रेखांकित किया है, जिसमें स्पष्ट कहा गया कि सार्वजनिक हस्तियां किसी विशेष समुदाय को धर्म, भाषा, जाति या क्षेत्र के आधार पर निशाना नहीं बना सकतीं। यह टिप्पणी केवल एक कानूनी निर्णय नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र की आत्मा की रक्षा करने वाला एक नैतिक संदेश भी है। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सौहार्द के लिए भाईचारा अनिवार्य है, और इस भाईचारे को बनाए रखने की जिम्मेदारी सबसे अधिक उन लोगों पर होती है जो सार्वजनिक जीवन में प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। चाहे वह राजनेता हों, सरकारी अधिकारी हों, कलाकार हों या सामाजिक प्रभाव रखने वाले अन्य व्यक्ति—उनके शब्द और उनके विचार समाज पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य केवल व्यक्तिगत अभिव्यक्ति नहीं होते, बल्कि वे समाज के वातावरण को प्रभावित करने वाले कारक बन जाते हैं। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब समाज में संवाद के नए माध्यम तेजी से विकसित हुए हैं। सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और जनसंचार के आधुनिक साधनों ने अभिव्यक्ति को सरल और व्यापक बना दिया है। अब कोई भी व्यक्ति कुछ ही क्षणों में लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकता है। यह शक्ति जहां लोकतंत्र को मजबूत करने का साधन है, वहीं इसका दुरुपयोग समाज में विभाजन और तनाव पैदा करने का कारण भी बन सकता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति—चाहे वह सरकारी हो या गैर-सरकारी—भाषण, मीम्स, कार्टून या चित्रों के माध्यम से किसी समुदाय को अपमानित या बदनाम नहीं कर सकता।

संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है और यह सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और गरिमा का अधिकार प्रदान करता है। संविधान का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के सम्मान और सुरक्षा मिले। जब कोई सार्वजनिक हस्ती किसी समुदाय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करती है, तो यह केवल उस समुदाय की भावनाओं को आहत नहीं करता, बल्कि संविधान के मूल सिद्धांतों को भी चुनौती देता है। न्यायालय ने अपने निर्णय में इस बात पर विशेष जोर दिया कि संविधान की रक्षा की शपथ लेने वाले व्यक्तियों की जिम्मेदारी और भी अधिक होती है, क्योंकि वे केवल स्वयं का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।

यह निर्णय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन की आवश्यकता को भी स्पष्ट करता है। भारत में हर नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार असीमित नहीं है। यह अधिकार दूसरों के सम्मान और समाज की शांति के साथ संतुलित होना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि कोई व्यक्ति दूसरों की गरिमा को ठेस पहुंचाए या समाज में विभाजन पैदा करे। न्यायालय का यह संदेश इस बात की याद दिलाता है कि स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है।

इस फैसले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि यह समाज में सकारात्मक संवाद को प्रोत्साहित करता है। जब प्रभावशाली लोग जिम्मेदारी के साथ बोलते हैं, तो वे समाज में सम्मान और सहयोग का वातावरण बनाते हैं। इसके विपरीत, जब वे विभाजनकारी भाषा का उपयोग करते हैं, तो यह समाज में अविश्वास और तनाव को बढ़ावा देता है। इसलिए न्यायालय का यह निर्णय केवल कानूनी दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत प्रासंगिक है।

भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत हमेशा से विविधता में एकता की रही है। यहां विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग सदियों से साथ रहते आए हैं। इस विविधता ने भारत को समृद्ध बनाया है और इसे एक अनोखी पहचान दी है। इस पहचान को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि समाज के सभी वर्ग एक-दूसरे के प्रति सम्मान और सहिष्णुता का भाव रखें। न्यायालय का यह निर्णय इसी भावना को मजबूत करता है और यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था इस सामाजिक संतुलन को कमजोर न करे।

इस फैसले का एक व्यापक प्रभाव यह भी हो सकता है कि भविष्य में सार्वजनिक जीवन में अधिक जिम्मेदार और संवेदनशील संवाद को बढ़ावा मिलेगा। जब न्यायालय इस प्रकार के स्पष्ट और मजबूत संदेश देता है, तो यह समाज में एक मानक स्थापित करता है। यह मानक केवल कानून के पालन तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह समाज के नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को भी प्रभावित करता है। इससे लोगों में यह जागरूकता बढ़ती है कि उनके शब्दों और कार्यों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ सकता है।

इस निर्णय से यह भी स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका केवल कानून की व्याख्या करने वाली संस्था नहीं है, बल्कि यह समाज के मूल्यों की रक्षा करने वाली एक महत्वपूर्ण संरक्षक भी है। न्यायालय के इस संदेश से यह विश्वास मजबूत होता है कि संविधान के सिद्धांतों की रक्षा हर परिस्थिति में की जाएगी और किसी भी प्रकार के भेदभाव या अपमान को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अंततः यह निर्णय केवल एक कानूनी टिप्पणी नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र की आत्मा की रक्षा करने वाला एक मार्गदर्शक संदेश है। यह हमें याद दिलाता है कि एक मजबूत राष्ट्र केवल आर्थिक या राजनीतिक शक्ति से नहीं बनता, बल्कि यह अपने नागरिकों के बीच आपसी सम्मान, विश्वास और भाईचारे की भावना से बनता है। जब समाज के प्रभावशाली लोग इस जिम्मेदारी को समझते हैं और अपने शब्दों का उपयोग सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से करते हैं, तो यह पूरे राष्ट्र के लिए एक प्रेरणा बनता है। न्यायालय का यह संदेश हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हम सभी, चाहे हम किसी भी भूमिका में हों, समाज में सम्मान, समानता और एकता को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। यही भावना भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखेगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, सम्मानजनक और समृद्ध समाज का निर्माण करेगी।

पहचान, नवाचार और भविष्य की दिशा का वैश्विक मंच बना सूरत का मीतराज IDPT

(जीएनएस)। गुजरात का सूरत शहर लंबे समय से व्यापार, उद्योग और सांस्कृतिक समृद्धि का केंद्र रहा है, लेकिन अब यह शहर शिक्षा और वैश्विक बौद्धिक संवाद के क्षेत्र में भी अपनी नई पहचान बना रहा है। इसी क्रम में मीतराज सार्वजनिक इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी (IDPT) में तीन दिवसीय बहुविषयक अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का भव्य शुभारंभ हुआ, जिसने सूरत को एक बार फिर वैश्विक ज्ञान और नवाचार के मानचित्र पर प्रमुख स्थान दिला दिया। सार्वजनिक यूनिवर्सिटी और सार्वजनिक एजुकेशन सोसायटी द्वारा आयोजित इस महत्वपूर्ण सम्मेलन ने कला, विज्ञान, वास्तुकला, संस्कृति, धर्म, तकनीक और समाज जैसे विविध क्षेत्रों के बीच संवाद का एक ऐसा मंच तैयार किया है, जहां भविष्य की दिशा तय करने वाले विचार जन्म ले रहे हैं।

25 फरवरी से 27 फरवरी तक चलने वाले इस सम्मेलन का उद्घाटन सार्वजनिक एजुकेशन सोसायटी कैंपस के तारा-मोती हॉल में अत्यंत गरिमामय वातावरण में किया गया। सम्मेलन का विषय 'डिजाइनिंग आइडेंटिटीजः इंटरसेक्शन्स ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, कल्चर, रिलिजन, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी' रखा गया है, जो अपने आप में यह संकेत देता है कि आज की दुनिया में पहचान केवल परंपरा या भौगोलिक सीमाओं से नहीं, बल्कि ज्ञान, तकनीक और सांस्कृतिक संवाद के समन्वय से बनती है। इस सम्मेलन का मूल उद्देश्य विभिन्न विषयों के बीच तालमेल स्थापित कर समाज की बदलती संरचना को समझना और एक ऐसा दृष्टिकोण विकसित करना है, जो भविष्य में समावेशी और टिकाऊ विकास को सुनिश्चित कर सके। सम्मेलन के पहले दिन यूरोप और अन्य देशों से आए प्रतिष्ठित विशेषज्ञों और विद्वानों ने अपने विचार साझा करते हुए वैश्विक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। बेल्जियम के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री Giuseppe Savino ने अपने संबोधन में वैश्विक अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना के बीच संबंधों पर प्रकाश डाला और बताया कि आधुनिक समाज में आर्थिक नीतियां केवल व्यापार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे सामाजिक पहचान और सांस्कृतिक विकास को भी प्रभावित करती हैं। रोमानिया की टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ क्लुज-नापोका से प्रोफेसर Ioana Moldovan और प्रोफेसर Tiganas Drago ने वास्तुकला और तकनीकी नवाचार के माध्यम से शहरी विकास की नई संभावनाओं पर चर्चा की।

सूरत की लक्ष्मीपति मिल में मॉक ड्रिल ने दिखाई सतर्कता और समन्वय की ताकत, आपदा से निपटने की तैयारी का सफल परीक्षण

(जीएनएस)। तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक शहर सूरत में सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को लेकर गंभीरता लगातार बढ़ती जा रही है। टेक्सटाइल उद्योग, जो इस शहर की आर्थिक धुरी माना जाता है, उसमें किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटना एक बड़ी चुनौती होती है। इसी चुनौती का सामना करने की तैयारियों को परखने के लिए पांडेसरा स्थित सिद्धि विनायक नोट्स एंड प्रिंट्स प्राइवेट लिमिटेड की लक्ष्मीपति मिल, यूनिट-1 में एक व्यापक ऑफ-साइट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसने यह साबित कर दिया कि सूरत का औद्योगिक तंत्र न केवल उत्पादन में अग्रणी है, बल्कि सुरक्षा के प्रति भी पूरी तरह सजग और प्रतिबद्ध है। इस मॉक ड्रिल का आयोजन सूरत लोकल जैसिस ग्रुप द्वारा किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य टेक्सटाइल मिल परिसर में संभावित अग्निकांड जैसी गंभीर आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों का परीक्षण करना था। डाई और प्रिंटिंग मिल परिसर में

आयोजित इस अभ्यास ने एक वास्तविक आपदा जैसी परिस्थिति का सजीव चित्र प्रस्तुत किया, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यदि भविष्य में कोई वास्तविक घटना होती है, तो सभी संबंधित एजेंसियां और कर्मचारी किस प्रकार त्वरित और प्रभावी कार्रवाई कर सकते हैं। इस प्रकार की मॉक ड्रिल केवल एक औपचारिक अभ्यास नहीं होती, बल्कि यह आपदा प्रबंधन प्रणाली की वास्तविक क्षमता और तत्परता का महत्वपूर्ण परीक्षण होती है।

मॉक ड्रिल के परिदृश्य के अनुसार, फैक्ट्री परिसर के फैब्रिक वेस्ट गोदाम में अचानक बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही फैक्ट्री की आंतरिक फायर टीम ने तत्काल कार्रवाई शुरू की और आग पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया। यह प्रारंभिक प्रतिक्रिया इस बात का संकेत थी कि फैक्ट्री के कर्मचारी और सुरक्षा टीम पहले से प्रशिक्षित और सतर्क हैं। हालांकि, आग की गंभीरता को देखते हुए यह स्पष्ट हो गया कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है। इसके बाद समीप स्थित कलरटेक्स फैक्ट्री की फायर ब्रिगेड को तुरंत बुलाया गया, जिसने घटनास्थल पर पहुंचकर आग बुझाने के प्रयासों को और तेज कर दिया। स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए ऑफ-साइट इमरजेंसी घोषित की गई और सूरत लोकल कैसिस ग्रुप को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही विभिन्न सरकारी और आपदा प्रबंधन एजेंसियों ने तत्काल प्रतिक्रिया दी और कुछ ही समय में सभी संबंधित टीमें घटनास्थल पर पहुंच गईं। इस दौरान लोकल कैसिस ग्रुप के चेयरमैन, एसडीएम, सूरत फायर विभाग के अधिकारी, उधना मामलतदार, फैक्ट्री निरीक्षक, सिविल अस्पताल की मेडिकल टीम, एंबुलेंस सेवा, जीपीसीबी और पांडेसरा पुलिस की टीमें एक साथ सक्रिय हो गईं। यह दृश्य इस बात का प्रमाण था कि आपदा की स्थिति में विभिन्न विभागों के बीच समन्वय कितना महत्वपूर्ण होता है और किस प्रकार सामूहिक प्रयास से किसी भी बड़ी दुर्घटना को नियंत्रित किया जा सकता है।

इस मॉक ड्रिल के दौरान राहत और बचाव कार्यों का पूरा अभ्यास किया गया। आग पर नियंत्रण पाने के साथ-साथ 'घायलों' को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर प्राथमिक उपचार दिया गया और उन्हें अस्पताल पहुंचाने की प्रक्रिया भी प्रदर्शित की गई।

सोना वायदा में 722 रुपये और चांदी वायदा में 4256 रुपये का ऊछालः क्रूड ऑयल वायदा में 2 रुपये का सुधार

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 242602.57 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 29376.42 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 213221.58 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का मार्च वायदा 40130 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 2018.12 करोड़ रुपये का हुआ। कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 23025.62 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 160977 रुपये के भाव पर खूलकर, 161652 रुपये के दिन के उच्च और 160163 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 159969 रुपये के पिछले बंद के सामने 722 रुपये या 0.45 फीसदी की मजबूती के साथ 160691 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया। गोल्ड-गिनी फरवरी वायदा 151 रुपये या 0.12 फीसदी बढ़कर 128821 रुपये प्रति 8 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। गोल्ड-पेटल फरवरी वायदा 52 रुपये या 0.32 फीसदी बढ़कर 16257 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। सोना-मिनी मार्च वायदा 158391 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 159245 रुपये और नीचे में 157750 रुपये पर पहुंचकर, 739 रुपये या 0.47 फीसदी बढ़कर 158330 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। गोल्ड-टेन फरवरी वायदा प्रति 10 ग्राम 160200 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 160373 रुपये और नीचे में 157025 रुपये पर पहुंचकर, 157946 रुपये के पिछले बंद के सामने 656 रुपये या 0.42 फीसदी बढ़कर 158602 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 265944 रुपये के भाव पर खूलकर, 270500 रुपये के दिन के उच्च और 263300 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 260744 रुपये के पिछले बंद के सामने 4256 रुपये या 1.63 फीसदी की तेजी के संग 265000 रुपये प्रति किलो हुआ। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 4955 रुपये या 1.88 फीसदी की तेजी के संग 268290 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 6030 रुपये या 2.29 फीसदी की मजबूती के साथ 268824 रुपये प्रति किलो बोला गया। मेटल वर्ग में 4943.21 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा फरवरी वायदा 22.1 रुपये या 1.88 फीसदी की तेजी के संग 1200.1 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि जस्ता फरवरी वायदा 2.65 रुपये या 0.81 फीसदी गिरकर 326.5 रुपये प्रति किलो हुआ। इसके सामने एल्यूमीनियम फरवरी वायदा 95 पैसे या 0.31 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 304.3 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा फरवरी वायदा 20 पैसे या 0.11 फीसदी बढ़कर 186.2 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

▸▸ कमोडिटी वायदाओं में 29376.42 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 213221.58 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 23025.62 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 40130 पॉइंट के स्तर पर

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 1404.65 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल मार्च वायदा 6044 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 6073 रुपये और नीचे में 5970 रुपये पर पहुंचकर, 2 रुपये या 0.03 फीसदी बढ़कर 6010 रुपये प्रति बैरल के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी मार्च वायदा 2 रुपये या 0.03 फीसदी लुढ़ककर 6008 रुपये प्रति बैरल बोला गया। इनके अलावा नैचुरल गैस मार्च वायदा 259.5 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 260.8 रुपये और नीचे में 257.4 रुपये पर पहुंचकर, 262.1 रुपये के पिछले बंद के सामने 3.1 रुपये या 1.18 फीसदी घटकर 259 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि नैचुरल गैस-मिनी मार्च वायदा 3.3 रुपये या 1.26 फीसदी औंधकर 259.1 रुपये प्रति एमएमबीटीयू पर आ गया। कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल फरवरी वायदा 940.7 रुपये पर खूलकर, 2.5 रुपये या 0.27 फीसदी बढ़कर 945 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 13181.36 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 9844.25 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 4366.69 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 228.96 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 47.50 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 293.31 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 675.87 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 698.10 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 2.34 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 9476 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 74660 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 31279 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 369670 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 62066 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 10148 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 17340 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 55281 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 18785 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 27252 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 40019 पॉइंट पर खूलकर, 40277 के उच्च और 40019 के नीचले स्तर को छूकर, 349 पॉइंट बढ़कर 40130 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल मार्च 6000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 3.4 रुपये की बढ़त के साथ 327.6 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मार्च 260 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 1.25 रुपये की गिरावट के साथ 17.3 रुपये हुआ।

सोना फरवरी 165000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 135.5 रुपये की गिरावट के साथ 348 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मार्च 300000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 448.5 रुपये की बढ़त के साथ 17878 रुपये हुआ। तांबा मार्च 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.25 रुपये की बढ़त के साथ 16.31 रुपये हुआ। जस्ता अप्रैल 372.5 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.8 रुपये की गिरावट के साथ 0.69 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल मार्च 6000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 5.6 रुपये की बढ़त के साथ 321.2 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मार्च 260 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 1.25 रुपये की बढ़त के साथ 17.7 रुपये हुआ।

सोना फरवरी 160000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 516 रुपये की गिरावट के साथ 1133.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मार्च 200000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 428 रुपये की गिरावट के साथ 2590 रुपये हुआ। तांबा मार्च 1200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 4.62 रुपये की गिरावट के

यात्रियों की सुविधा और विकास की नई दिशाः वडोदरा मंडल में उपभोक्ता सलाहकार समिति की बैठक में भविष्य की रेल सेवाओं पर हुआ मंथन

(जीएनएस)। रेलवे केवल एक परिवहन माध्यम नहीं है, बल्कि यह देश की जीवनरेखा है, जो लाखों लोगों के सपनों, जरूरतों और उम्मीदों को जोड़ती है। यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और संतुष्टि को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल में इस वर्ष की पहली मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में किया गया। यह बैठक केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं थी, बल्कि यह रेलवे प्रशासन और यात्रियों के बीच संवाद, सहयोग और सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई, जिसमें रेलवे की वर्तमान उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक की शुरुआत समिति के सचिव एवं वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक नरेन्द्र कुमार द्वारा सभी सदस्यों के स्वागत के साथ हुई। इसके बाद समिति के अध्यक्ष और मंडल रेल प्रबंधक राजू भडके ने एक संक्षिप्त प्रस्तुति के माध्यम से मंडल में चल रहे विकास कार्यों, यात्री सुविधाओं और नई परियोजनाओं की जानकारी साझा की। उनकी प्रस्तुति में यह स्पष्ट दिखाई दिया कि वडोदरा मंडल लगातार आधुनिकता, सुविधा और दक्षता की दिशा

में तेजी से आगे बढ़ रहा है, ताकि यात्रियों को बेहतर और आरामदायक यात्रा अनुभव मिल सके। इस बैठक में विशेष रूप से भारतीय रेलवे की महत्वाकांक्षी अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी दी गई। इस योजना के तहत स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को विश्वस्तरीय अनुभव मिल सके। स्टेशन परिसरों को अधिक स्वच्छ, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाया जा रहा है, जिसमें बेहतर प्रतीक्षालय, स्वच्छ शौचालय, डिजिटल सूचना प्रणाली, आधुनिक टिकटिंग सुविधाएं और दिव्यांगजनों के लिए विशेष व्यवस्था शामिल है। यह प्रयास रेलवे को केवल एक यात्रा साधन नहीं, बल्कि एक समग्र सेवा प्रदाता के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बैठक के दौरान यह भी बताया गया कि प्रतापनगर-जोबट सेक्शन पर ट्रेनों की गति बढ़ाने के लिए आवश्यक तकनीकी सुधार किए जा रहे हैं। इससे यात्रियों का समय बचेगा और यात्रा अधिक सुगम और तेज होगी। इसके साथ ही स्टेशनों पर दिव्यांग फ्रेंडली सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे हर यात्री, चाहे वह किसी भी शारीरिक स्थिति में हो, सम्मान और सुविधा के साथ यात्रा कर सके। यह पहल रेलवे की समावेशी सोच और सामाजिक जिम्मेदारी को दर्शाती है।

यात्रियों की बढ़ती संख्या और ट्रैफिक दबाव को ध्यान में रखते हुए उधना स्टेशन के बोझ को कम करने के लिए उत्राण स्टेशन को सैटेलाइट स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह कदम न केवल भीड़ प्रबंधन में सहायक होगा, बल्कि यात्रियों को वैकल्पिक और सुविधाजनक यात्रा विकल्प भी प्रदान करेगा। इससे रेलवे नेटवर्क की क्षमता और दक्षता दोनों में वृद्धि होगी, जिससे यात्रियों को अधिक सुगम और संतुलित सेवा मिल सकेगी।

सूरत के नए सिविल अस्पताल में संविदा कर्मचारियों की मौजूदगी से जुड़े घोटाले की जांच की मांग की गई है

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। सूरत के नए सिविल अस्पताल में, श्रेणी-3 तकनीकी सहायक, प्रयोगशाला सहायक, नकद विभाग के कर्मचारी और श्रेणी-4 सफाईकर्मी, नैनी और वार्ड बॉय के पद संविदा पर भरे जाते हैं। इन संविदा पदों पर अपेक्षित संख्या से कम कर्मचारियों की भर्ती के कारण वार्डों और अन्य विभागों में सफाई का काम ठीक से नहीं होता है और ठेकेदार तथा सूरत के सिविल अस्पताल के जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी धन का गबन किया जा रहा है। अस्पताल में प्रतिदिन कितने कर्मचारियों को ड्यूटी पर रखा जाना चाहिए, इसके लिए कोई नियम या मानक नहीं है। सूरत के नए सिविल अस्पताल के रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर, ठेकेदार के कर्मचारी और साथ ही साथ नए सिविल अस्पताल के सेवानिवृत्त कर्मचारी, जो वर्तमान में संविदा पर काम कर रहे हैं, इन सभी की मिलीभगत से उपस्थिति में गड़बड़ी की जा रही है और सरकारी धन का गबन किया जा रहा है। प्रतिदिन कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है और कितने कर्मचारियों को ड्यूटी पर रखा गया है, इसका निर्णय अगले दिन किया

जाता है। इसलिए यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि कर्मचारी ने पिछले दिन अपना कर्तव्य निभाया था या नहीं। और किसी को भी यह जानने में रुचि नहीं है।

शून्य त्रुटि एजेंसी

सूरत के नए सिविल अस्पताल के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को उनके पद के अनुसार वेतन मिलता है। ऑल इंडिया सफाई मजदूर कांग्रेस के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत के. सोलंकी की मांग है कि

कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति की गहन जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए ।

राजस्थान की गांव ग्वाला योजनाः 10,000 रुपये के वेतन पर ग्वालों की भर्ती शुरू

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। आजकल राजस्थान सरकार की एक योजना खूब चर्चा में है, जिसका नाम है गांव ग्वाला योजना। इस योजना के तहत गाय चराने वाले चरवाहों की भर्ती की जा रही है और उन्हें इसके लिए भुगतान भी किया जाएगा। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कोटा जिले के रामगंज मंडी के 14 गांवों में चरवाहों की नियुक्ति की है। सरकार ने पशुपालन की प्राचीन परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए यह नई योजना शुरू की है।

शून्य त्रुटि एजेंसी

ये चरवाहे प्रतिदिन गांव की सभी गायों को सामूहिक रूप से चरागाह में ले जाएंगे और शाम को उन्हें वापस घर ले आएंगे। गायों को पूरे दिन चरने के लिए छोड़ दिया जाएगा और शाम को उन्हें वापस गांव के घरों में भेज दिया जाएगा। प्रत्येक 70 गायों के लिए एक चरवाहा नियुक्त किया गया है। यदि गायों की संख्या बढ़ती है, तो उस गांव में अन्य चरवाहों को भी नियुक्त किया जाएगा। प्रत्येक चरवाहे को गायों को चराने के लिए 10,000 रुपये का वेतन मिलेगा। यह योजना गांव के दानदाताओं के सहयोग से चलाई जा रही है।

गुजरात के शहरों में स्वदेशी मलों के आयोजन से 'वोकल फॉर लोकल' को प्रोत्साहन

▸▸ गुजरात शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत 15 मार्च तक 152 नगर पालिका क्षेत्रों में स्वदेशी मेले आयोजित किए जाएंगे

▸▸ अब तक 38 नगर पालिका क्षेत्रों में स्वदेशी मेलों का प्रारंभ, 1 लाख से अधिक लोग पहुँचे, 83 लाख से अधिक की बिक्री हुई

(जीएनएस)। गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए 'वोकल फॉर लोकल' मंत्र का अनुकरण करते हुए देश के नागरिकों का स्वदेशी उत्पाद अपनाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में गुजरात में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने ग्रामीण एवं शहरी कारीगरों, हस्तकलाकारों तथा छोटे उद्योगों को समर्थन देने के लिए अनेक नई पहलें की हैं। 'गुजरात आत्मनिर्भर यात्रा', 'जी-मैत्री योजना', 'महिला उद्योग सहायता योजना' जैसे कार्यक्रमों द्वारा राज्य में स्वदेशी उत्पादों को नई ऊर्जा मिल रही है। इसके अतिरिक्त; शहरी विकास एवं शहरी गृह निर्माण विभाग अंतर्गत गुजरात शहरी आजीविका मिशन द्वारा स्वदेशी मेलों (शॉपिंग फेस्टिवल) का राज्यव्यापी आयोजन किया जा रहा है; जिनके माध्यम से स्थानीय कारीगरों, स्वयंसहायता समूहों तथा छोटे व्यापारियों को एक मजबूत प्लेटफॉर्म मिल रहा है।

उल्लेखनीय है कि गत वर्ष दशहरा से दीपावली के दौरान राज्य के 16 शहरों में प्लास्टिक फ्री 'स्वदेशी फेस्टिवल' का सफल आयोजन किया गया था। इन मेलों में 40.50 लाख से अधिक लोग आए थे और 10 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री दर्ज हुई थी। इस सफलता को आगे बढ़ाते हुए अब राज्य के सभी नगर पालिका क्षेत्रों में स्वदेशी मेलों (शॉपिंग फेस्टिवल) का आयोजन

किया गया है; जिनके द्वारा स्वयंसहायता समूहों (एसएचजी), स्थानीय कारीगरों, कलाकारों तथा छोटे व्यापारियों को अपने स्वदेशी उत्पाद प्रदर्शित करने व बेचने का उत्तम अवसर मिलेगा।

15 मार्च तक राज्य के 152 नगर पालिका क्षेत्रों में स्वदेशी मेले आयोजित होंगे

15 मार्च, 2026 तक राज्य के सभी 152 नगर पालिका क्षेत्रों में स्वदेशी मेलों का आयोजन किया गया है। इस आयोजन के तहत 1500 से अधिक स्टॉल स्वयंसहायता समूहों को आवंटित किए गए हैं, जबकि स्ट्रीट वेंडर्स को 1400 से अधिक स्टॉल दिए गए हैं। खान-पान के 1500 स्टॉल तैयार किए जा रहे हैं और अन्य कारीगरों को अपने स्वदेशी उत्पादों की बिक्री करने के लिए 1650 से अधिक स्टॉल आवंटित किए गए हैं।

अब तक 38 नगर पालिका क्षेत्रों में स्वदेशी मेलों का प्रारंभ, 83 लाख रुपए से अधिक की बिक्री

राज्य में अब तक 38 नगर पालिका क्षेत्रों में स्वदेशी मेले शुरू किए गए हैं; जिनमें अहमदाबाद, भावनगर, गांधीनगर, राजकोट, सूरत तथा वडोदरा अंचलों के विभिन्न नगर पालिका क्षेत्र शामिल हैं। इस दौरान 1 लाख से अधिक लोग स्वदेशी मेलों में पहुँचे और 83 लाख रुपए से अधिक के उत्पादों की बिक्री हुई है। यह सफलता दर्शाती है कि नागरिक 'वोकल फॉर लोकल' पहल के साथ उत्साहपूर्वक जुड़ रहे हैं। स्वदेशी मेले केवल व्यापार के लिए प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए उल्लेखनीय प्रयास हैं।

भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी दृढ़तापूर्वक मानते हैं कि स्वदेशी तथा आत्मनिर्भर भारत विकसित भारत के निर्माण का राजमार्ग है। इसका अनुकरण करते हुए गुजरात सरकार इसके लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि आगामी समय में देश का प्रत्येक नागरिक 'वोकल फॉर लोकल' का वाहक बने और स्वदेशी के मंत्र का अनुकरण करे।

लाखाबावल स्टेशन पर भावनगर–ओखा–भावनगर एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज अस्थायी रूप से रद्द

(जीएनएस)। राजकोट मंडल के अंतर्गत आने वाले लाखाबावल रेलवे स्टेशन पर नए फुट ओवर ब्रिज (FOB) के निर्माण कार्य के चलते यात्री सुरक्षा एवं कार्य की सुचारु प्रगति सुनिश्चित करने हेतु ट्रेन संख्या 19209/19210 भावनगर–ओखा–भावनगर एक्सप्रेस का स्टॉपेज अस्थायी रूप से रद्द किया गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार लाखाबावल स्टेशन पर उक्त ट्रेन का ठहराव दिनांक 26 फरवरी, 2026 से 5 मार्च, 2026 तक रद्द रहेगा। निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत ट्रेन का नियमित स्टॉपेज पुनः बहाल कर दिया जाएगा। रेल यात्रियों से अनुरोध है कि वे इस अस्थायी फेरबदल को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं। ट्रेनों के परिचालन से संबंधित नवीनतम एवं अद्यतन जानकारी के लिए यात्री कृपया भारतीय रेल की आधिकारिक वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in का अवलोकन करें, जिससे किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।

पश्चिम रेलवे चलायेगी अहमदाबाद और मंगलुरु के बीच स्पेशल ट्रेन

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे होली फेस्टिवल के दौरान यात्रियों की मांग व सुविधा को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद और मंगलुरु स्टेशनों के बीच विशेष किराए पर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाएगी। इस ट्रेन का विवरण निम्नानुसार हैः

ट्रेन संख्या 09424/09423 अहमदाबाद – मंगलुरु साप्ताहिक स्पेशल [8 फेरे]

ट्रेन संख्या 09424 अहमदाबाद-मंगलुरु साप्ताहिक स्पेशल 27 फरवरी और 06,13,20 मार्च 2026 (शुक्रवार) को अहमदाबाद से 16.00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 20.00 बजे मंगलुरु पहुँचेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 09423 मंगलुरु-अहमदाबाद साप्ताहिक स्पेशल 28 फरवरी और 07,14,21 मार्च 2026 (शनिवार) को मंगलुरु से 22.30 बजे प्रस्थान करेगी और सोमवार को 02.15 बजे अहमदाबाद पहुँचेगी।

यह ट्रेन मार्ग में दोनों दिशाओं में नडियाद, आणंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, वापी, वसई रोड,भिवंडी रोड, पनवेल, पेन, रोहा, मानगांव, खेड़, चिपलून, सावर्डा, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, राजापुर रोड, वैभववाड़ी रोड, कणकवली, सिंधुदुर्ग, कुडाल, सावंतवाड़ी रोड, थिविम, करमाली, मडगांव, काणकोण, कारवार, अंकोला, गोकर्ण रोड, कुमटा, मुर्डेश्वर, भटकल, मूकाम्बिका रोड बैंदूर, कुंन्दापुरा, उडुपि, मुल्की और सुरतकल स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास और सामान्य द्वितीय श्रेणी के डिब्बे होंगे।

ट्रेन संख्या 09424 की बुकिंग सभी पीआरएस काउंटरों और IRCTC वेबसाइट पर शुरू है। ट्रेनों के समय, ठहराव और संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए, यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

चीन के रेस्तरां में कोबरा-क्वीन सांप के व्यंजन वायरल हो रहे हैं, 180 डॉलर का किंग कोबरा व्यंजन खबरों में छाया हुआ है

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। चीन में कई ऐसे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पका हुआ चिकन, मटन और कीड़े-मकोड़े परोसे जाते हैं। लेकिन एक अनोखा रेस्टोरेंट, जो लंबे समय से चल रहा है, हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। एक ट्रैवल ब्लॉगर द्वारा बनाए गए वीडियो ने लोगों में जिज्ञासा जगा दी है। इस रेस्टोरेंट के मेनू में सांप के कई व्यंजन हैं, जिनमें किंग कोबरा भी शामिल है। यह रेस्टोरेंट एक महिला चलाती है, जिसे स्थानीय लोग कोबरा क्वीन कहते हैं। बाहर से देखने पर यह रेस्टोरेंट एक साधारण ढाबे जैसा लगता है, लेकिन यहाँ लकड़ी के बक्सों में जीवित सांप रखे जाते हैं। ग्राहक इन लकड़ी के बक्सों में से अपनी पसंद का सांप चुनकर खा सकते हैं।

शून्य त्रुटि विज्ञापन

फिर सांप को तलकर कुरकुरे चिप्स की तरह परोसा जाता है या उबालकर सूप या सब्जी के रूप में परोसा जाता है। व्यंजन की कीमत आपके द्वारा चुने गए सांप के अनुसार तय होती है। किंग कोबरा से बने व्यंजन की कीमत 180 डॉलर या लगभग 16,500 रुपये है। यहां सांप के अंगों से बने स्वास्थ्यवर्धक पेय भी उपलब्ध हैं। हांगकांग में सांप के व्यंजनों को एक अनोखी खाद्य संस्कृति के रूप में बढ़ावा दिया गया है। हालांकि, कई लोग इसे खतरनाक और अमानवीय मानते हैं।

गुजरात 1 मार्च, 2026 को महात्मा मंदिर में तीसरी सेमीकनेक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा

▸▸ सेमीकनेक्ट कॉन्फ्रेंस के तीसरे संस्करण में वैश्विक सीईओ और नीति निर्माता हिस्सा लेंगे

▸▸ माइक्रोन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, सीजी सेमी, केन्स और उनके वैश्विक भागीदार गुजरात के सेमीकंडक्टर क्षेत्र के विकास में शामिल होंगे ' '

(जीएनएस)। गांधीनगर : गुजरात सरकार आगामी 1 मार्च, 2026 को गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में सेमीकनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 के तीसरे संस्करण की मेजबानी करेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व से प्रेरित इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन गुजरात सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और गुजरात स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स मिशन (जीएसईएम) की ओर से किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री के टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर होने के आह्वान ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र को भारत के ग्रोथ एजेंडा के केंद्र में स्थापित किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), रेल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री

अर्जुन मोढवाडिया की उपस्थिति में इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे।

इस कॉन्फ्रेंस की थीम 'गुजरात : इंडियाज गेटवे टू सिलिकॉन' (गुजरात : सिलिकॉन के लिए भारत का प्रवेशद्वार) है, जो भारत की सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के प्रमुख केंद्र के तौर पर स्थापित होने की राज्य की महत्वाकांक्षा को प्रतिबिंबित करता है। गुजरात अपने मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक कॉरिडोर और निवेशक-अनुकूल नीतियों के साथ, भारत की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च क्षमताओं को गति देने में मुख्य भूमिका निभाने के लिए तैयार है। यह कॉन्फ्रेंस वैश्विक सेमीकंडक्टर सीईओ, नीति निर्माताओं और उद्योग अग्रणियों को एक साथ लाएगी, जो वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति को मजबूत करने की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे।

इस दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस के तहत मुख्य भाषण, थीमैटिक पैनल्स और अंतरराष्ट्रीय राउंडटेबल का आयोजन किया गया है। पहले दिन नेक्स्ट जनरेशन सेमीकंडक्टर रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग, धोलेरा और साणंद जैसे हब के लिए लॉजिस्टिक्स और निर्यात की तैयारी, भविष्य के कौशल के लिए कार्यबल का विकास जैसे सत्र आयोजित किए जाएंगे। सत्रों के दौरान होने वाली चर्चाओं में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स आधार को मजबूत बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिनमें प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से लेकर रेजिलिएंट कंपोनेंट इकोसिस्टम शामिल हैं। समानांतर सत्रों में माइक्रोन सप्लायर्स राउंडटेबल, जापान और ताइवान के साथ कंट्री-स्पेसिफिक राउंडटेबल और 'फ्रॉम सिलिकॉन टू स्टूडेंट्स : बिल्डिंग इंडियाज सेमीकंडक्टर फ्यूचर' (सिलिकॉन से विद्यार्थियों तक : भारत के सेमीकंडक्टर भविष्य का निर्माण) शीर्षक के अंतर्गत शिक्षा और आउटरिच पर एक सेमीनार का आयोजन होगा।

दूसरे दिन, धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन-एसआईआर) में गाइडेड टूर का आयोजन किया गया है, जो जीएसईएम, डीआईसीडीएल और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर से आयोजित होगा। इस गाइडेड टूर से प्रतिनिधियों को गुजरात के महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को स्वयं देखने का अवसर मिलेगा।

इस कॉन्फ्रेंस में प्रतिष्ठित वक्ताओं को आमंत्रित किया गया है, जिनमें टीईपीएल के सीईओ और एमडी डॉ. रणधीर ठाकुर, माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ श्री संजय मेहरोत्रा, सीजी सेमी के चेयरमैन श्री जी.सी. चतुर्वेदी, केन्स टेक्नोलॉजी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट श्री रमेश कुन्हीकन्नन, सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट एंड मैटेरियल्स इंटरनेशनल (सेमी) के सीईओ श्री अजित मनोचा और जॉर्जिया टेक के एमेरिटस प्रोफेसर डॉ. राव तुम्माला शामिल हैं। उनकी उपस्थिति गुजरात के सेमीकंडक्टर विजन में दुनिया के बढ़ते विश्वास को दर्शाती है। यह भारत को उन्नत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लीडर बनाने के प्रधानमंत्री के स्वप्न को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस पहल को माइक्रोन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और केन्स सेमीकॉन जैसी जानीमानी सेमीकंडक्टर कंपनियों तथा जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (जेट्रो-जापान), कोरिया व्यापार-निवेश संवर्धन एजेंसी (कोटरा-कोरिया), इन्वेस्ट इंडिया, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, सेमी, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन (आईईएसए), इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (ईएलसीआईएनए), इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए) और मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (एमईडीईपीसी) जैसे नॉलेज पार्टनर्स का समर्थन मिला है। उनकी भागीदारी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गुजरात में बढ़ते अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं राष्ट्रीय प्रगति को दर्शाती है।

गुजरात सेमीकनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 एक ऐतिहासिक कार्यक्रम बनेगा, जो सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत के विकास की आधारशिला रखेगा। यह कॉन्फ्रेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के प्रधानमंत्री के विजन और गुजरात को नवाचार एवं निवेश का केंद्र बनाने की मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। यह दिखाता है कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में नेतृत्व करने के लिए तैयार है। इस कॉन्फ्रेंस की थीम ('गुजरात : इंडियाज गेटवे टू सिलिकॉन') से पता चलता है कि गुजरात वैश्विक चिप निर्माताओं के साथ ही स्थानीय उद्योगों, उद्यमियों एवं विद्यार्थियों का इस परिवर्तनकारी समय में योगदान देने के लिए स्वागत करता है।

वडनगर रेलवे स्टेशन का निरीक्षणः मंडल रेल प्रबंधक ने यात्री सुविधाओं एवं नई लाइन परियोजना की प्रगति की समीक्षा

(जीएनएस)। मंडल रेल प्रबंधक, अहमदाबाद श्री वेद प्रकाश ने दिनांक 25.02.2026 को वडनगर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने रिले रूम, रूट रिले इंटरलॉकिंग (RRI), मास्टर केबिन, बुकिंग काउंटर, फुट ओवर ब्रिज, प्लेटफॉर्म एवं कैफेटेरिया सहित विभिन्न यात्री सुविधाओं का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए, ताकि स्टेशन पर यात्री सुविधाओं को और बेहतर बनाया जा सके।

निरीक्षण के दौरान मंडल रेल प्रबंधक ने बताया कि वडनगर स्टेशन पर रेल डिब्बों में पानी भरने हेतु कोच वाटरिंग सिस्टम की व्यवस्था की जा रही है। इस सुविधा के शुरू होने से ट्रेनों में वडनगर स्टेशन से ही पानी भरा जा सकेगा, जिससे यात्रियों को यात्रा के दौरान पर्याप्त जल उपलब्ध हो सकेगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने स्टेशन पर जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की तथा स्टेशन के समीप स्थित रेलवे क्रॉसिंग को चौड़ा करने की उनकी मांग पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया।

इस अवसर पर महेसाणा–वरेठा सेक्शन के वरेठा रेलवे स्टेशन पर अंबाजी नई लाइन परियोजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक कार्य के सफल समापन की जानकारी दी गई। यह कार्य आबूरोड–तारंगा हिल नई लाइन रेलखंड की भविष्य की कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वरेठा स्टेशन पर मुख्य लाइन पर स्थित पुराने डेड एंड ट्रैक को हटाकर नई एलाइनमेंट पर स्थानांतरित

किया गया तथा उसे नई बिछाई गई लाइन से जोड़ा गया। संशोधित यार्ड लेआउट के अनुसार नई डेड एंड लाइन की भी व्यवस्था की गई है, जिससे भविष्य में तारंगा हिल दिशा में मुख्य लाइन विस्तार का मार्ग प्रशस्त होगा।

यह समस्त कार्य दो दिवसीय ब्लॉक के दौरान सुरक्षित एवं योजनाबद्ध तरीके से संपन्न किया गया। इस दौरान रेल कटिंग, डेड एंड ट्रैक हटाना एवं शिफ्टिंग, नई लाइन से लिंकिंग, ग्लूड जॉइंट निर्माण, वेल्डिंग, बैलेस्टिंग, पैकिंग, क्रॉसओवर की मशीन टैम्पिंग तथा अन्य आवश्यक ट्रैक समायोजन कार्य किए गए। विद्युत (TRD) विभाग द्वारा ओएचई वायरिंग हटाने एवं पुनः वायरिंग, एटीडी शिफ्टिंग/कटिंग, बॉन्डिंग कार्य तथा टॉवर वैगन से निरीक्षण किया गया। टर्नआउट क्षेत्र क्लियर होने के पश्चात सिग्नल एवं दूरसंचार (S&T) विभाग द्वारा प्वाइंट परीक्षण, पुनः संयोजन एवं कमीशनिंग कार्य प्रगति पर है।

इस परियोजना से भविष्य में आबूरोड–तारंगा हिल रेलखंड की सुदृढ़ कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी, जिससे यात्रियों को सुरक्षित, सुगम एवं अधिक सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध होगी। साथ ही अंबाजी एवं तारंगा हिल क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा स्थानीय व्यापार एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। बेहतर यार्ड संरचना एवं तकनीकी उन्नयन से ट्रेनों के संचालन में सुगमता आएगी तथा समयपालन में भी सुधार होगा।

वडोदरा मंडल पर मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल पर मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति (DRUCC) की इस वर्ष की पहली बैठक का आयोजन मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय, वडोदरा में किया गया। बैठक के प्रारंभ में समिति के सचिव व वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री नरेन्द्र कुमार ने सभी सदस्यों का स्वागत किया। इसके बाद समिति के अध्यक्ष एवं वडोदरा मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके द्वारा संक्षिप्त प्रजेंटेशन के माध्यम से सभी सदस्यों को मंडल की गतिविधियों एवं विकास कार्यों से अवगत कराया गया। श्री भडके ने माननीय सदस्यों को मंडल पर अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकसित किये जा रहे स्टेशनों की जानकारी दी। उन्होंने प्रतापनगर- जोबट क्षेत्र पर ट्रेनों

की सेक्शन स्पीड बढ़ाने के साथ-साथ स्टेशनों पर प्रदान की जा रही विभिन्न सुविधाओं के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि इसमें दिव्यांग फ्रेंडली सुविधा के दृष्टिकोण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उन्होंने आगे बताया कि उधना स्टेशन पर यात्रियों के ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए उत्राण स्टेशन को सैटेलाइट स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने आगामी होली के त्यौहार को देखते हुए वडोदरा मंडल द्वारा चलायी जा रही गोरखपुर एवं मऊ के लिए स्पेशल ट्रेन की जानकारी भी दी।

इस दौरान समिति सदस्यों द्वारा अपने अपने क्षेत्र की रेल समस्याओं, ट्रेनों के स्टॉपेज, विस्तार,नई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने तथा मंडल के स्टेशनों पर बेहतर यात्री सुविधाएं प्रदान करने के लिए अपने सुझाव दिये । मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके ने सभी सदस्यों के सुझावों पर शीघ्र उचित कार्यवाही का आश्वासन देते हुए कहा कि यात्री सुविधाओं का विकास वडोदरा मंडल की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

इस आयोजित बैठक में माननीय सदस्यों में सर्वश्री निपम आर देसाई, श्री भरत आर गुप्ता, श्री नीलेशकुमार आई पटेल, श्री ईश्वर पी सज्जन, श्री वंदनकुमार बी पंड्या, श्री ओमकारनाथ तिवारी, श्री एम. हबीब लोखंडवाला, श्री इंद्रवदन एस जोशी, श्री व्यास मितलभाई कौशिकभाई और श्री राकेशचंद्र वी व्यास उपस्थित थे। बैठक के दौरान वडोदरा मंडल के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

सूरत में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई से रियल एस्टेट जगत में हलचल मिरिक और ओपेरा ग्रुप पर छापेमारी से उजागर हो सकते हैं करोड़ों के राज

(जीएनएस)। सूरत के रियल एस्टेट सेक्टर में उस समय अचानक हलचल मच गई, जब वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतिम चरण में आयकर विभाग ने शहर के प्रमुख बिल्डर समूहों मिरिक ग्रुप और ओपेरा ग्रुप के ठिकानों पर व्यापक सर्च ऑपरेशन शुरू किया। बुधवार तड़के शुरू हुई इस कार्रवाई ने न केवल बिल्डर लॉबी, बल्कि पूरे औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्र में हलचल पैदा कर दी। करीब 80 अधिकारियों की एक बड़ी टीम ने एक साथ कई स्थानों पर छापेमारी कर दस्तावेजों, डिजिटल रिकॉर्ड और वित्तीय लेन-देन से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्यों की जांच शुरू की। इस कार्रवाई को वित्तीय वर्ष के अंत में टैक्स टारगेट की पूर्ति और अघोषित आय के स्रोतों पर नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार, आयकर विभाग को उन्नत डेटा एनालिटिक्स सिस्टम के माध्यम से कुछ संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों की जानकारी मिली थी। जांच के दौरान यह संकेत मिले कि कुछ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में बुकिंग के समय बड़ी मात्रा में नकद लेन-देन किए गए थे, जिनका पूरा विवरण आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज नहीं था। इस प्रकार के लेन-देन आमतौर पर टैक्स चोरी और

अघोषित आय से जुड़े होते हैं, जिससे सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचता है। इसी आधार पर विभाग ने यह सर्च ऑपरेशन शुरू किया, ताकि इन संदिग्ध लेन-देन की वास्तविकता का पता लगाया जा सके और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सके।

आयकर विभाग की टीम ने ओपेरा ग्रुप के नवसारी स्थित प्लॉटिंग और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के साथ-साथ मिरिक ग्रुप के महत्वाकांक्षी धोलेरा एसआईआर प्रोजेक्ट्स से जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच शुरू की। अधिकारियों ने पिछले तीन वर्षों के सेल्स रजिस्टर, रॉ अकाउंट्स, बुकिंग रिकॉर्ड और अन्य वित्तीय दस्तावेजों को जब्त किया है। इन दस्तावेजों की तुलना संबंधित कंपनियों द्वारा दाखिल किए गए आयकर रिटर्न से की जाएगी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या आय और लेन-देन का सही विवरण प्रस्तुत किया गया था या नहीं। इस प्रक्रिया से संभावित टैक्स चोरी और अघोषित आय का खुलासा होने की संभावना है।

जांच की आंच केवल बिल्डर कंपनियों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि जमीन से जुड़े बिचौलियों और ब्रोकर्स तक भी पहुंच गई है। जानकारी के अनुसार, कुछ प्रमुख ब्रोकर्स के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई, जहां से महत्वपूर्ण दस्तावेज और रिकॉर्ड बरामद हुए हैं। प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि जमीन की वास्तविक कीमत से अधिक राशि नकद में लेकर स्टाम्प ड्यूटी से बचने का प्रयास किया गया। इस प्रकार की गतिविधियां न केवल टैक्स चोरी की श्रेणी में आती हैं, बल्कि यह रियल एस्टेट बाजार की पारदर्शिता को भी प्रभावित करती हैं। इस छापेमारी के दौरान आयकर विभाग की तकनीकी टीम ने डिजिटल डेटा पर भी विशेष ध्यान दिया। अधिकारियों ने सर्वर, कंप्यूटर सिस्टम और क्लाउड स्टोरेज से बड़ी मात्रा में डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए हैं। जांच के दौरान कुछ डायरी और नोटबुक भी बरामद हुई हैं, जिनमें कोडवर्ड में वित्तीय लेन-देन दर्ज किए गए हैं।